कृषि विश्लेषण जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

ज्येष्ठ-आषाढ़ 2078, जून 2021

सर्वसुलभ टीकाकरण की बाधाएं

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

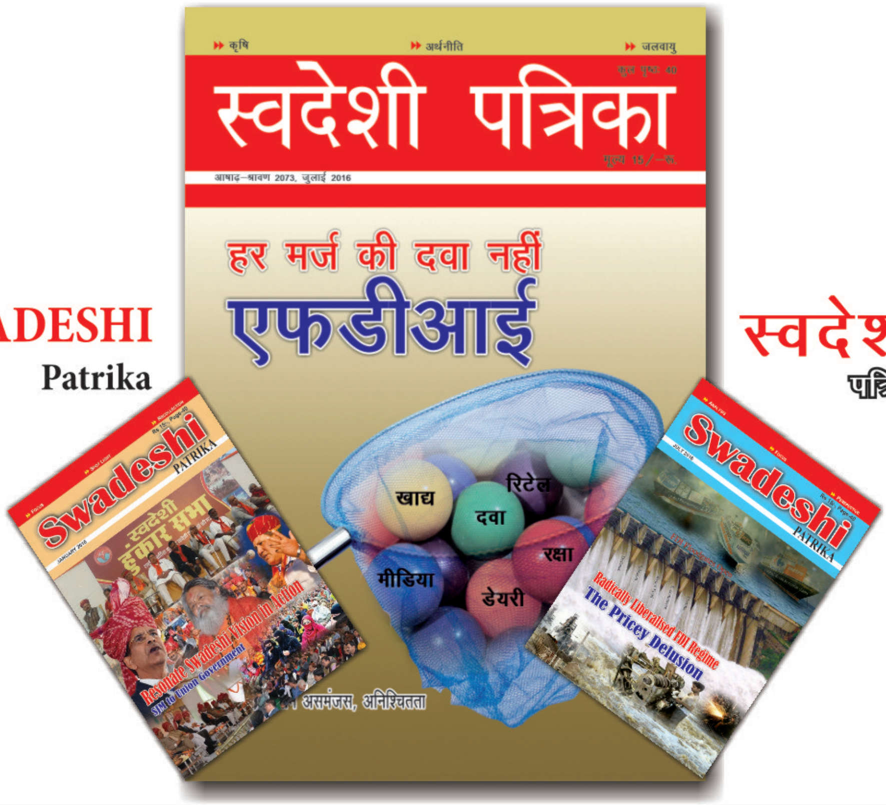

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :**	**150/-**
आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :**	**1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–29, अंक–6

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2078 जून 2021

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

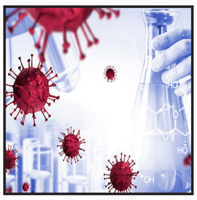

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–6

सर्वसुलभ टीकाकरण की बाधाएं

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
कोविड–19 का जैविक आक्रमण एवं चीन
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

11 आवरण कथा
गरीब को भी मिले विकास में हिस्सेदारी
.... देविन्दर शर्मा

13 आवरण कथा
कोरोना इफेक्टः आर्थिक मोर्चे पर भारत कई देशों से बेहतर
.... विक्रम उपाध्याय

15 आवरण कथा
कोविड काल में छोटे उद्योगों का कठिन सफर
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

17 आवरण कथा
महामारी से लड़ने में प्रभावी होगा वन नेशन, वन हेल्थ सिस्टम
.... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

19 आवरण कथा
अंकों के खेल से बाहर निकलने का समय
.... निरंजन सिंह

21 आवरण कथा
नयी स्वास्थ्य क्रांति की दरकार
.... अभिषेक प्रताप सिंह

23 मुद्दा
देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है विदेशी सोशल मीडिया
.... अनिल तिवारी

25 शिक्षा
तलाशने होंगे परीक्षा के वैकल्पिक माध्यम
.... दुलीचंद कालीरमन

27 जल प्रबंधन
बिन पानी सब सूनः परंपरागत जल प्रबंधन की उपेक्षा का दुष्परिणाम
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

29 पडताल
हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत है?
.... सलिल सरोज

29 स्वदेशी गतिविधियां
राष्ट्रीय परिषद बैठक (तरंग) – (जून 5–6, 2021)

पाठकनामा

बच्चों से दूर होती शिक्षा

कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश भर के शैक्षणिक संस्थाएं फिलहाल बंद है। लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों ने वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन कक्षा का आयोजन शुरू कर दिया है। इसके कुछ फायदे और ज्यादा नुकसान दोनों पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। किसी भी कक्षा का सत्र पीछे न हो और नियमित समय पर छात्र–छात्राएं सत्र पूरा करके आगे के सत्र में प्रवेश पा सकें, यह कमोबेश ऑनलाइन कक्षा से संभव हो पाया है। लेकिन सच यह है कि इस दौरान देशभर के आम लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। किसान और मजदूर वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जिसे देखते हुए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में से एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि पिछले वर्ष के परीक्षा फार्म शुल्क को अगले वर्ष के परीक्षा फार्म शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इससे इग्नू से पढ़ाई करने वाले छात्र–छात्राओं को कुछ आर्थिक राहत जरूर मिली है। यह एक सराहनीय फैसला है।

ऐसे में अन्य राज्यों के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, इससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी खर्च होने के बजाय अन्य खर्च बच रहा है। दूसरी ओर शिक्षक और विद्यार्थियों को अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराकर कक्षा में शामिल होना पड़ रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि शिक्षक और विद्यार्थियों को दोहरा आर्थिक शुल्क का वहन करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए देश के सभी शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक शुल्क के अलावा विभिन्न शुल्क में केवल ऑनलाइन कक्षा संचालन होने तक कटौती करके छात्र छात्राओं को आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए। वरना छात्र छात्राओं के परिवार को भी आर्थिक रूप से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

वहीं दूसरी तरफ कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में बच्चे तेजी से चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनमें मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का डर बढ़ा है। महामारी में स्कूल बंद है और बच्चे घर में कैद हैं, जिन बच्चों ने खेल को अपने कैरियर के रूप में चुना था उनकी स्थिति और बदतर है। भविष्य को देखते हुए सरकार को इस मोर्चे पर सार्थक पहल करनी चाहिए।

संजय कुमार, देवली, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हजारों वर्षों से लाखों–करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन, योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को यह भारत की अनुपम देन है। योग, कोविड–19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है।

रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, भारत

केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन, सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हो, जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

इसरो, डीआरडीओ और आईआईटी जैसे देश के अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम लागत वाली बैटरी तकनीक के विकास की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

नितिन गड़करी, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, भारत

दुनिया की 7.87 अरब की आबादी को कोरोना के चंगुल से बचाने हेतु टीकों और दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेटेंट कानूनों में ढील देने की जरूरत है, भले ही यह सीमित अवधि के लिए ही क्यों न हो।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

चीन के खिलाफ लामबंदी

हाल ही में जी–7 देशों (अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान) का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसके सम्मेलनों में स्थायी आमंत्रित के रूप में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इस वर्ष के मेजबान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चार देशों – भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, को भी आमंत्रित किया था।

रूस 1997 से 2014 तक जी–7 का औपचारिक सदस्य रहा, लेकिन इसमें चीन को कभी शामिल या आमंत्रित नहीं किया गया है। पिछले सम्मेलनों में चीन पर चर्चा भी नहीं के बराबर ही होती थी, लेकिन इस बार लगभग सारी चर्चा चीन पर ही केंद्रित रही।

जानकारों का कहना है कि इस सम्मेलन में '3–सी' यानी कोरोना, क्लाइमेट (पर्यावरण) और चीन छाये रहे। चीन विरोधी सुरों के कई उदाहरण इस सम्मेलन में मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु लोकतांत्रिक और पारदर्शी राष्ट्रों की भूमिका पर बल दिया, जिसका सीधा मतलब यह था कि समाधान में हमें चीन से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि चीन न तो लोकतांत्रिक है और न ही पारदर्शी। सम्मेलन में महामारी के उद्गम की जांच हेतु प्रयास तेज करने पर भी जोर दिया गया।

बाइडेन प्रशासन के एक आला अधिकारी ने चीन के अपारदर्शी, कमजोर पर्यावरण, श्रम मानकों और जोर–जबरदस्ती वाले व्यवहार का जवाब देने की जरूरत पर बल दिया, जिसके कारण दूसरे मुल्कों को भारी नुकसान हो रहा है। हांगकांग की स्वायत्तता, चीन के शिनजियांग प्रदेश में मानवाधिकार और 'ताइवान स्ट्रेट' के आसपास शांति और स्थिरता के मुद्दों को भी उठाया गया। ऐसे में सम्मेलन को ऐतिहासिक माना जा सकता है।

दुनियाभर में लोग चीन को इस महामारी का कारण मान रहे हैं, लेकिन पहली बार इस सम्मेलन में महसूस हुआ कि शक्तिशाली देश पूरे जोश से चीन के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं, और उन मुद्दों को केंद्र में लाया जा रहा है, जो चीन के कम्युनिस्ट शासकों को बिल्कुल पसंद नहीं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ समय से चीन को अरब महासागर और प्रशांत महासागर में चुनौती देने के उद्देश्य से अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह 'क्वाड' सैन्य अभ्यास कर रहा है।

चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को इससे अंकुश लगा है। यह न केवल भारत को समुद्र से चीन से मिलने वाली चुनौती का एक सशक्त जवाब है, बल्कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की महत्वपूर्ण शर्त भी है। इस संबंध में ताइवान की सुरक्षा हेतु जी–7 सम्मेलन का स्पष्ट वक्तव्य चीन को सीधा चुनौती देने वाला है।

चीन पिछले कई सालों से बेल्ट रोड परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, जिस पर 100 से अधिक मुल्कों ने हस्ताक्षर किया है। इनमें न केवल जी–7 से इटली शामिल है, बल्कि विशेष आमंत्रित सदस्यों से दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया भी हैं। जी–7 शिखर सम्मेलन में इसके मुकाबले 'बी 3 डब्लू' (बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड) पहल का उद्घोष हुआ। गौरतलब है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आगे बढ़ायी जा रही है।

अमेरिका और भारत दोनों ही चीनी परियोजना के विरोधी रहे हैं, लेकिन इसे रोक पाना दो वर्ष पहले तक लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे में जी–7 का प्रयास एक बड़ी पहल माना जा रहा है। यह इंगित करना जरूरी है कि यदि चीन की महत्वाकांक्षी योजना पर अंकुश लगता है और अमेरिका समर्थित 'बी 3 डब्लू' को बढ़ावा दिया जाता है, तो भारत को रणनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा लाभ मिल सकता है।

चीनी परियोजना में सिर्फ चीन के बैंकों और संस्थाओं (अधिकांश सरकारी) और चीनी निर्माण कंपनियों का ही बोलबाला था। अपारदर्शी और विभेदकारी समझौतों के चलते उसमें शामिल देशों पर न केवल कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, बल्कि चीन का राजनीतिक दखल भी उन देशों में बढ़ गया था। ऐसे में अधिक पारदर्शी 'बी 3 डब्लू' उन देशों के लिए लाभकारी होगा ही, भारत की निर्माण कंपनियों को भी बड़ा बिजनेस मिलेगा और वैश्विक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इससे चीन के दबदबे को भी विराम लगेगा।

काफी समय से चीन औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से दुनिया के बाजारों पर कब्जा तो करता ही जा रहा था, अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते अपने पड़ोसी देशों को भी डरा–धमकाकर उनकी भूमि हथियाने का प्रयास कर रहा था। उसके सभी पड़ोसी देश जो अभी तक भयभीत थे, चीन को मिलती चुनौती के मद्देनजर अब संबल प्राप्त करेंगे। पिछले लगभग पांच वर्षों से अमेरिका व भारत समेत कई देश अपने उद्योगों और अर्थव्यवस्था के प्रति अधिक संवेदनशील और संरक्षणकारी हो रहे हैं। भारत में 'मेक इन इंडिया' और पिछले एक साल से 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रयास चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ही है। ऐसे में अब चीन को अपने निर्यातों को बरकरार रखना आसान नहीं होगा।

पिछले कुछ समय से चीन अपनी शक्ति और दबदबे के चलते अधिक दंभी भी हो गया था, लेकिन दुनिया का आक्रामक रुख देखकर अब उसने अपना रुख भी थोड़ा नरम किया है, ताकि वह अपने प्रति बढ़ते हुए रोष को कम कर सके। कहा जा सकता है कि दुनिया में चीन के खिलाफ बढ़ती लामबंदी चीन के लिए शुभ संकेत नहीं है। उसे अपनी हेकड़ी, आर्थिक और सैन्य आक्रामकता पर विराम लगाना पड़ेगा। शायद यही दुनिया में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सर्वसुलभ टीकाकरण की बाधाएं

आज पूरी दुनिया जिस महामारी से बार–बार जूझ रही है, उसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। बीमारी का प्रमाण इतना अधिक हो जाता है कि बड़े–बड़े अमीर मुल्क भी अपनी अपार आर्थिक शक्ति और सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के बावजूद अत्यंत असहाय दिखाई देते हैं। भारत ने स्वयं अप्रैल–मई के माह में ऐसी स्थिति का सामना किया, जब हमें ऑक्सीजन, अस्पताल बेड और यहां तक कि दवाइयों की भारी किल्लत से जूझना पड़ा।

आज दुनिया में वैक्सीन इस समस्या के समाधान का रामबाण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल सहित 6 मुल्कों ने अपनी अधिकांश वयस्क जनसंख्या को वैक्सीनयुक्त करते हुए अपनी जनता को मास्क लगाने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। इसलिए माना जाता है कि यदि हम अपनी समस्त जनसंख्या को टीकाकृत कर देंगे तो हम भी इस महामारी से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान को न्यूनतम कर सकेंगे।

वैक्सीन का असमान वितरण

अगर दुनिया में वैक्सीन की उपलब्धता और वितरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि वैक्सीन की अलग–अलग मुल्कों में अत्याधिक असमानता है। ऐसे में यदि दुनिया से इस महामारी को समाप्त करना उद्देश्य हो तो सारे विश्व का टीकाकरण करना जरूरी है। पोलियो उन्मूलन अभियान में ध्येय वाक्य रखा गया कि 'यदि एक भी बच्चा छूट गया – सुरक्षा चक्र टूट गया'। कोरोना महामारी में भी वही बात लागू होती है। समझना होगा कि दुनिया के सभी देश किसी न किसी प्रकार से दूसरों से जुड़े हुए हैं। यदि कोई भी देश पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट गया तो यह महामारी फिर से सिर उठा सकती है।

गौरतलब है कि जब यह महामारी का प्रकोप दुनिया में हुआ और यह लगा कि टीकाकरण इसकी रोकथाम का उपाय हो सकता है, तभी से भारत में स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के प्रयासों से वैक्सीन विकास हेतु काम शुरू हो गया था। भारत में दो स्वदेशी प्रयास फलीभूत हो चुके हैं, जिसमें से एक भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कोवैक्सीन के निर्माण को लेकर है, जिसके द्वारा अगस्त से दिसंबर के बीच 35 करोड़ वैक्सीन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा स्वदेशी प्रयास हैदराबाद की बायलॉजिकल–ई नाम की कम्पनी की वैक्सीन का था, इसके द्वारा भी इस वर्ष अगस्त और दिसंबर के बीच 30 करोड़ वैक्सीन

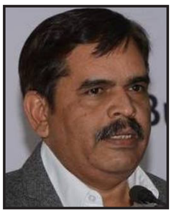

दुर्भाग्य का विषय है कि भारत और साउथ अफ्रीका के मानवता हेतु 'ट्रिप्स वेवर' के प्रयासों के मार्ग में कुछ यूरोपीय देश और कुछ अन्य विकसित देश बाधाएं खड़ी कर रहे हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

भारत सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सिरेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ऑक्स्फर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से भारत में वैक्सीन विकास का एक बड़ा प्रयास हुआ। भारत सरकार के अनुमान के अनुसार अगस्त और दिसंबर के बीच सिरेम इंस्टीट्यूट 75 करोड़ वैक्सीन डोज निर्माण करके उपलब्ध करवा देगी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि मौजूदा वर्ष के अंत तक संपूर्ण जनसंख्या को टीकाकृत कर दिया जाएगा।

लेकिन विश्व में है चिंता व्याप्त

भारत में वैक्सीन निर्माण की भरपूर क्षमता और सरकार के प्रारंभ से ही किए गए प्रयासों के कारण भारत में टीकाकरण की गति अन्य देशों की तुलना में अधिक रही है, लेकिन देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण संपूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण का लक्ष्य थोड़ा दूर है। लेकिन यह सही भी है कि इस वर्ष के अंत तक हम अपना लक्ष्य पूर्ण कर लेंगे, लेकिन यदि शेष दुनिया की बात करें तो ध्यान में आता है कि भारत समेत दुनिया के कुछ देशों को छोड़कर उनमें वैक्सीन निर्माण की क्षमता ही नहीं है। भारत तो दुनिया भर के लिए वैक्सीन का प्रमुख स्रोत रहा है। लेकिन दूसरे मुल्कों में चिंता व्याप्त होना स्वभाविक ही है, क्योंकि वे वैक्सीन निर्माण तो कर नहीं सकते लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए दुनिया की चुनिंदा कंपनियों पर उन्हें आश्रित होना पड़ेगा। दुनिया में चल रही पेटेंट व्यवस्था और अन्य प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के चलते कंपनियां अत्यंत महंगी कीमत पर वैक्सीन बेच रही है। गौरतलब है कि जहां भारत में प्रारंभिक दौर में सरकार द्वारा अधिकांशतः मुफ्त और प्राइवेट सेक्टर में 250 रू. की दर से वैक्सीन की डोज लगाई गई। अभी भी वैक्सीन सरकार द्वारा रुपए 150 रुपए प्रति डोज की दर से ख़रीदी जा रही है फाइजर और मोडरेना सरीखी कंपनियां 20 से 50 डॉलर (यानी 1500 से 3750 रुपए) प्रति डोज की दर से वैक्सीन बेच रही हैं। गरीब देशों की सरकारें अथवा लोग इतनी महंगी वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है। सर्वसुलभ वैक्सीन के लिए कीमत सबसे बड़ी बाधा है। समझ सकते है कि वैक्सीन की ऊंची कीमत के पीछे पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को पार करने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में यह गुहार लगाई है कि इस महामारी के दौरान इस पेटेंट व्यवस्था से मुक्ति दी जाए। इस गुहार का नाम है 'ट्रिप्स वेवर' यानी ट्रिप्स से मुक्ति।

क्या है ट्रिप्स वेवर?

अक्टूबर 2020 में भारत और साउथ अफ्रीका ने संयुक्त रूप से विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव रखा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इसके लिए वैक्सीन और आवश्यक दवाओं पर एक निश्चित समय (जिसका निर्धारण किया जाए) के लिए ट्रिप्स के प्रावधानों से छूट दी जाए ताकि इन वैक्सीन और दवाइयों का पर्याप्त उत्पादन और उसकी उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु इस प्रयास को 120 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन पहले से ही मिल चुका है। मई माह के अंत में इस हेतु प्रस्तावक देशों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें इन देशों ने एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और इस प्रस्ताव में मांग की गई कि कम से कम 3 वर्षों के लिए वैक्सीन और कोविड की दवाइयों हेतु ट्रिप्स के प्रावधानों से छूट दी जाए और इसके साथ ही वैक्सीन और दवाओं के उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट से मुक्ति भी सुनिश्चित हो।

समझना होगा कि ट्रिप्स समझौता जहां बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान देता है वही उसमें यह प्रावधान भी रखा गया था कि स्वास्थ्य संकट, महामारी आदि की स्थिति में ट्रिप्स के प्रावधानों में ढ़ील देकर मानवता के उद्देश से काम किया जा सकता है। साथ ही विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र में इस विषय पर और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया था। दोहा घोषणा में यह स्पष्ट किया गया है कि जन स्वास्थ्य संकट, महामारी, भीषण बीमारियों की स्थिति में सदस्य देशों की संप्रभु सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि दवाइयों हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सस्ती दरों पर दवाइयां अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं।

यानी कहा जा सकता है कि पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल पर एकाधिकार, ट्रेड सीक्रेट जैसे विषयों के कारण गरीब मुल्कों के लिए वैक्सीन और दवाओं की सुलभता में बाधाएं आ रही है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारत और साउथ अफ्रीका के मानवता हेतु ट्रिप्स वेवर के इन प्रयासों के मार्ग में कुछ यूरोपीय देश और कुछ अन्य विकसित देश बाधाएं खड़ी कर रहे हैं।

लेकिन संतोष का विषय यह है कि अमरीकी प्रशासन ने अपना पहले का रुख बदला है और अब उन्होंने वैक्सीन के लिए भारत वह साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर के प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है। आगे आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कंपनियों के लाभों के सामने मानवता जीतेगी या नहीं। क्या पेटेंट मुक्त वैक्सीन और दवाएं वास्तव में बनाई जा सकेंगी या गरीब मुल्कों को इन कंपनियों से महंगी दवाएं ही खरीदनी पड़ेगी। समय की मांग है कि समाज की सज्जन शक्तियां पेटेंट मुक्त वैक्सीन और दवाइयों को सुनिश्चित करने हेतु जन दबाव बनाकर मानवता की जीत सुनिश्चित करें। ❑❑

कोविड–19 का जैविक आक्रमण एवं चीन

विगत 16 माह में विश्व में 17.5 करोड़ व भारत में 2.85 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 37 लाख से अधिक पूरे विश्व में व 3.4 लाख से अधिक लोग भारत में कोविड–19 से अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं। मृतकों की दस गुनी संख्या में कोरोना संक्रमण से मुक्ति के बाद भी कोविड–19 के उत्तरवर्ती प्रभावों के कारण संक्रमण युक्त होने के बाद भी विकलांगता अर्द्ध–विकलांगता, व कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं। कोरोना व लॉकडाउन आदि से 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 42 खरब डालर की प्रत्यक्ष क्षति हो चुकी है और वर्ष 2021 में 65 खरब डालर की प्रत्यक्ष क्षति सम्भावित है। परोक्ष क्षति इससे कहीं अधिक है। विश्व की अधिकांश शेष जनता भी आज कोविड–19 से संभावित संक्रमण के भय से त्रस्त है।

चीन में उद्गम व उनकी उत्तरदेयताः

चीन द्वारा इस वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित किये जाने के षड़यंत्र की चर्चाओं को एक बार निराधार मान लेने के बाद भी यह निर्विवादतः सत्य है कि चीन में इस वायरस का उद्गम हुआ और चीन ने इस संबंध में अपने वैधानिक कर्त्तव्यों की अवहेलना की जिससे यह संकट विश्व भर में फैला। चीन में यह वायरस 17 नवम्बर 2019 को ही चिन्हित हो गया था। दिसंबर के अंत में इससे मानव मृत्यु भी घट चुकी थी और मध्य दिसम्बर तक हुनान के सामुद्रिक खाद्य बाजार के अनेक ग्राहकों व कर्मचारियों में इस वायरस का प्रकोप भी प्रकट हो चुका था। लेकिन, चीन इन सभी बातों को छिपाता रहा। फरवरी 14 तक उसके 1700 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित भी हो गये थे। चीन द्वारा अपने विधिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए इन जानकारियों को षडयंत्र–पूर्वक छिपाए रखने से ही यह महामारी विश्व भर में फैली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ''अन्तर्राष्टीय स्वास्थ्य नियमनों'' के अधीन ऐसे संक्रामक रोग की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनिवार्यतः देने के लिए चीन विधानतः बाध्य था। इसलिए, सारी जानकारियों को छिपाने के लिए अन्तर्राष्टीय कानूनों के अधीन चीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोरोना प्रभावित 200 से अधिक देशों के प्रति उत्तरदायी व उनका दोषी है।

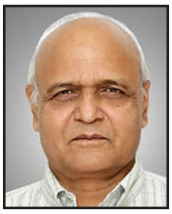

चीन द्वारा इस वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित किये जाने के षड़यंत्र की चर्चाओं को एक बार निराधार मान लेने के बाद भी यह निर्विवादतः सत्य है कि चीन में इस वायरस का उद्गम हुआ और चीन ने इस संबंध में अपने वैधानिक कर्त्तव्यों की अवहेलना की, जिससे यह संकट विश्व भर में फैला।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन, इसकी क्षतिपूर्ति उससे कराया जाना विधि सम्मत है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमनों (इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन्स) के अनुच्छेद 6 के अधीन, किसी देश की सीमाओं में उपजे जन स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक जोखिम की सूचना 24 घण्टे की अवधि में विश्व स्वास्थ्य संगठन को देनी होती है। इन्हीं नियमनों के अनुच्छेद–7 के अधीन, स्वास्थ्य संबंधी उस जोखिम का कारण व उद्गम कुछ भी हो, उसके उद्गम वाले देश को, उसकी सीमा में वैश्विक जनस्वास्थ्य के प्रति संकट की द्योतक प्रत्येक छोटी–बड़ी घटना के संबंध में, जो भी तथ्य उपलब्ध हैं उन्हें अनिवार्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन को उपलब्ध कराने होते हैं। चीन ने अपने इन दोनों ही वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए विश्व समुदाय द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति के लिए चीन को बाध्य किया जाना विधि सम्मत है। वैश्विक चित्ति उस दिशा में अग्रसर होती भी दिखलाई देती है। लन्दन स्थित इण्टरनेशनल काउन्सिल ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स के अनुसार भी चीन पर इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का असन्दिग्ध दायित्व है।

चीन का विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमनों के उलंघन का अपराध व दायित्व अत्यन्त गंभीर है क्योंकि, आज तक भी चीन इस वायरस संबंधी, कई उपलब्ध जानकारियाँ छिपाए हुये है। इसकी जाँच हेतु अन्य देशों के बहुपक्षीय निरीक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने को भी तैयार नहीं है। वस्तुतः नवम्बर 17, 2019 को चीन में इस नवीन वायरस के उपजने के साथ ही इसकी सूचना चीन को 24 घण्टे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को दे देनी थी। दिसम्बर 26, 2019 को तो चीनी संचार माध्यमों में एक अनाम लैब टेक्नीशियन के संदर्भ से सार्स रोग से 87 प्रतिशत समानता रखने वाले लक्षणयुक्त इस नवीन कोरोना वायरस के समाचार तक प्रसारित हो गये थे। तब भी चीन उन समाचारों को रोकने में ही लगा रहा। दिसंबर 30 को तो चीनी 'वुहान सेण्ट्रल हास्पीटल' के वैज्ञानिक 'ली वेनलियांग' ने इस कोरोना वायरस के संकट की स्पष्ट शब्दों में चेतावनी ही दे दी थी। उसे व ऐसी सूचनायें देने वाले अन्य वैज्ञानिकों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था या बलात चुप कर दिया गया। चार दिनों के उत्पीड़न के बाद 'ली' को तो स्वयं अपने को झूठा स्वीकार करने तक को बाध्य कर लिया था। इण्टरनेट पर भी इस वायरस की कोई सूचनाएँ साझा करने के विरुद्ध जनवरी एक को सिन्हुआ समाचार ऐजेन्सी के माध्यम से सभी नेटीजन्स (नेट पर सूचना साझा करने वालों तक) कड़ी चेतावनी भी दे डाली।

दिसम्बर 31 को विश्व को और भी गुमराह करने के लिए वुहान म्यूनिसिपल कमीशन तक ने जानबूझ कर यह झूठ भी प्रसारित कर दिया कि इस रोग का ''मानव से मानव''में संक्रमण ही नहीं होता है। चीन के ही अनुचित प्रभाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने 21 जनवरी को यह तक कह दिया कि इस वायरस का प्रभाव अत्यन्त हल्का (माइल्ड) है व यह पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। इसके लिये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी गंभीर लापरवाही–जन्य दायित्व उपजता है जिसे षडयंत्रपूर्ण दुष्प्रचार ही कहा जायेगा।

वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वाइरसः

विश्व के कुछ अलग शोधकर्त्ताओं के एक स्वतंत्र समूह, ''डीसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनॉमस सर्च टीम इनवेस्टिगेटिंग कोविड–19'' (ड्रैस्टिक) के विशेषज्ञों के अनुसार तो कोरोना वायरस चीन के मछली बाजार से नहीं वरन, वुहान की लैब से निकला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चीनी का अनुवाद कर अपने स्तर पर किए ड्रैस्टिक के संघन अन्वेषणों के अनुसार इसका उद्गम साल 2012 से ही हो गया था। तब छह खदान श्रमिकों को यन्नान के मोजियांग में उस माइनशाफ्ट को साफ करने भेजा गया था जहां चमगादड़ों का आतंक था। उन श्रमिकों की वहां मौत हो गई। साल 2013 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. शी झेंगली और उनकी टीम माइनशाफ्ट से सैंपल अपने लैब में लाई।

शी का कहना है कि श्रमिकों की मौत गुफा में मौजूद फंगस से हो गई। इसके विपरीत ड्रैस्टिक के अनुसार शी को एक अज्ञात कोरोना स्ट्रेन मिला जिसे उन लोगों ने आरएसबीटीकोव/4491 का नाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साल 2015–17 के पेपर में इसका विस्तार से विवेचन है। विवादित प्रयोगों से इस वायरस को बहुत अधिक संक्रामक बना दिया। यह थ्यौरी बताती है कि एक लैब की गलती कोविड–19 के विस्फोट का कारण बनी। इस बात को भारतीय वैज्ञानिक दंपत्ति डा. राहुल व डा. मोनाली ने खुलासा किया।

चीनी वायरोलॉजिस्ट ने कहा–फाउची के इमेल से लीक की बात सच साबित हुई

एक चीनी वायरोलॉजिस्ट ने कहा है कि अमेरिका के शीर्ष कोरोना वायरस सलाहकार एंथनी फाउची के ई–मेल साबित करते हैं कि कोरोना की उत्पत्ति वुहान के लैब से ही हुई थी। डॉक्टर ली–मेंग यान जो उन लोगों में से थीं, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना के वुहान की लैब से लीक हुए होने की बात कही थी। डॉक्टर ली–मेंग यान कोरोना पर शोध करने वाले पहले लोगों में से एक थीं और उन्होंने खुलासा किया था कि बीजिंग पर इस मामले को छुपाने का

आरोप लगाने के बाद उन्हें छिपने के लिए मजबूर किया गया।

सुनियोजित जैविक हथियार?

इन दस्तावेजों में एक ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर भी मिलने का दावा किया गया है, जिसे वर्ष 2015 में चीन के 18 सैन्य वैज्ञानिकों और हथियारों के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया था। इसका शीर्षक है, 'अननेचुरल ओरिजिन ऑफ़ सार्स ऐंड न्यू स्पीशीज ऑफ़ मैन मेड वायरसेज ऐस जेनेटिक बायोवेपंस' या दूसरे शब्दों में कहें तो इस शीर्षक का मतलब है कि ये पेपर सार्स और कोरोना वायरस की अप्राकृतिक तरीक़े से उपजी नई प्रजातियां और उनकी मदद से जैविक हथियार बनाने की संभावनाओं पर तैयार किया गया था। इन वैज्ञानिकों ने लिखा था कि कोरोना वायरस नाम के वायरस परिवार में, 'कृत्रिम रूप से बदलाव करके इंसानों की बीमारी वाले वायरस तैयार किए जा सकते हैं और फिर इन्हें हथियार बनाकर इनका इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कभी पहले देखा नहीं गया।'

विचारणीय बात यह है कि कोविड–19 महामारी के लिए ज़िम्मेदार वायरस भी एक कोरोना वायरस ही है, जो सबसे पहले चीन के वुहान शहर में सामने आया था और इसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया था। इस दस्तावेज़ में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया था कि, लैब में तैयार कोरोना वायरस की नई प्रजातियां, 'जैनेटिक हथियारों के नए युग' की शुरुआत करेंगे। ये लेख लिखने वालों ने ऐसे जैविक हथियारों की कल्पना की थी, जिससे 'दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है।'

इस दस्तावेज़ और अन्य खुफिया जानकारियों के आधार पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जांच करके 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट दें।

वर्ष 1993 में ही चीन ने स्वयं से यह घोषणा भी की थी कि, उसके आठ अनुसंधान केंद्रों में, 'जैविक हथियार संबंधी राष्ट्रीय आत्मरक्षात्मक अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम' चल रहे हैं। इनमें वैक्सीन बनाने वाले केंद्र जैसे कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी शामिल है। चीन की सिनोफार्म कंपनी अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए इसी केंद्र की सुविधाओं का प्रयोग करती है। उसके बाद से वर्ष 2015 के एक अध्ययन में पाया गया है कि चीन की सरकार के रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े 12 केंद्र और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े 30 सुविधाएं ऐसीं हैं जो जैविक हथियारों पर रिसर्च, उनके विकास, उत्पादन, परीक्षण या भंडारण के काम से जुड़ी हुई हैं। इनमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल नहीं था। हालांकि, अमेरिका ने हाल ही में ये पता लगाया है कि, 'वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ़ वायरोलॉजी ने चीन की सेना के साथ मिलकर गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम किया है, और उनकी रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया है।' यही नहीं, चीन का ये संस्थान, 'उसकी सेना की ओर से 2017 से ही ऐसे गोपनीय रिसर्च में भी शामिल रहा है, जिसमें जानवरों पर प्रयोग किए गए हैं।'

कोरोना वायरस मानव निर्मितः

एचआईवी वैक्सीन पर काम कर चुके ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डल्गलिश और नार्वे के वैज्ञानिक डॉ बिर्गर सोरेनसेन ने साथ मिलकर कोरोना वायरस के टीकों पर अध्ययन के लिए जब कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो किसी भी वायरस में बिना लैब छेड़छाड़ के नहीं मिलता। नार्वे के वैज्ञानिक डॉ बिर्गर सोरेनसेन के मतानुसार, कोरोना वायरस के स्पाइक में 4 अमीनो एसिड हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इससे वायरस के स्पाइक मानव कोशिकाओं के नेगेटिव चार्ज वाली हिस्सों को मजबूती से जकड़कर संक्रमण फैलाते हैं। प्राकृतिक रूप से तीन अमीनो एसिड एक स्पाइक पर मिलना बहुत दुर्लभ है। मौजूदा वायरस में यह चार हैं, जो उनके अनुसार कृत्रिम रूप से बनाए जाने पर ही संभव है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना एक प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम वायरस है।

कोविड–19 टीके का 2020 का पेटेण्ट आवेदन–एक बड़ा प्रमाणः

दी वीकेण्ड आस्ट्रेलियन पत्रिका के अनुसार, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक वैज्ञानिक झाऊ यूसेन ने 24 फरवरी, 2020 को ही अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कोविड–19 के टीके के पेटेण्ट के लिए आवेदन कर दिया था। यूसेन की मई 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। ऐसे में लगता है कि चीन ने अपनी जनसंख्या को इस जैविक हथियार से सुरक्षित रखने का टीका आरंभ में ही विकसित कर लिया।

चीन से क्षतिपूर्ति की मांग आवश्यकः

इन परिस्थतियों को देखते हुए जहाँ कोरोना के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को 100 खरब (10 ट्रिलियन) डालर की प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुयी है। उसकी सीमा में उपजे इस वायरस व इसकी सूचनाएँ छिपाने के कारण इस क्षति की पूर्ति चीन से कराई जानी चाहिए अन्यथा चीन पर सभी देशों को मिल कर सामूहिक रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाने का निर्णय लेना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों की अवहेलना जनित संकट के लिए चीन स्पष्ट रूप से दोषी है। यह उसकी घोर विकृति विश्व–द्रोह कही जाने योग्य है। ❑❑

गरीब को भी मिले विकास में हिस्सेदारी

पीड़ादायक विद्रूपता यह कि महामारी के चलते विश्वभऱ में लगभग 14.4 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे धंस गए हैं। गरीबी पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आंकड़े बताते हैं कि 8.5 करोड़ के इजाफे के साथ भारत अब नाइजीरिया को पीछे छोड़कर विश्वभर में अत्यंत गरीबों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है।

– देविंदर शर्मा

जब से कोविड की पहली लहर ने मुल्कों को लॉकडाउन की ओर ढकेला है, केंद्रीय बैंकों ने, खासकर अमीर देशों के, कुल मिलाकर 9 ट्रिलियन डालर की अतिरिक्त करंसी छापी है। इनके पीछे मुख्य मंतव्य वैश्विक महामारी से मजबूर हुई आर्थिकी को संबल देना है। फाइनेंशियल टाइम्स के 16 मई के अंक में मार्गन स्टेनली इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट की मुख्य वैश्विक नीतिकार रुचिर शर्मा के अनुसार मौजूदा महामारी के दौरान दिए गए आर्थिक प्रोत्साहनों ने उलटे बड़े अमीरों को और ज्यादा अमीर किया है क्योंकि अधिकतर धन वित्तीय मंडियों में जाता है, जहां से यह अत्यंत धनाढ्य वर्ग के खजाने में पहुंच जाता है। अनुमान है कि इस अवधि में विश्व के चोटी के अमीरों की कुल धन–दौलत में 5 से 13000 करोड़ डॉलर के बीच इजाफा हुआ है। कोई हैरानी नहीं कि आज शेयर बाजार पैसे से पटे पड़े हैं, जबकि अधिकांश देश अपनी आर्थिकी को मंदी से बाहर निकालने को संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ादायक विद्रूपता यह कि महामारी के चलते विश्वभऱ में लगभग 14.4 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे धंस गए हैं। गरीबी पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आंकड़े बताते हैं कि 8.5 करोड़ के इजाफे के साथ भारत अब नाइजीरिया को पीछे छोड़कर विश्वभर में अत्यंत गरीबों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। पहले ये लोग गरीबी रेखा के आसपास रहने के बावजूद किसी न किसी तरह अपना गुजर–बसर किए हुए थे। लेकिन कोविड–19 की दूसरी लहर के बाद, जो और भी ज्यादा घातक है, इस संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी होगी।

शायद हमें यह अहसास नहीं है कि विश्वभर में गरीबी रेखा से नीचे लोगों को उबारने में महज 100 अरब डॉलर की जरूरत है, जो महामारी के लिए जारी किए गए कुल वैश्विक आर्थिक प्रोत्साहन का अंश मात्र ही है, जबकि आर्थिकी को संबल देने के नाम पर दिया गया अधिकांश धन गरीबों के काम आने की बजाय खरबपतियों का खजाना भरने में ज्यादा सहायक हुआ है। यह पहली बार नहीं है कि हैरान करने वाली इतनी मात्रा में दिया गया अतिरिक्त धन अप्रत्यक्ष रूप से शीर्ष अमीरों की तिजोरी तक जा पहुंचा हो। इस हेतु पिछले

कई सालों से संपन्न देशों के केंद्रीय बैंक अतिरिक्त करंसी छाप रहे हैं। लेकिन जो बात आज तक हमें समझाई नहीं गई कि अमीरों को देने के लिए तो सरकारों के पास तमाम पैसा और तरीका होता है, लेकिन गरीबी से लड़ने को दुनिया के पास यथेष्ठ धन कभी नहीं हुआ। वैश्विक महामारी से निपटने में जितना धन कुल मिलाकर जारी किया गया है, यदि उसका अंशमात्र भी वहां पहुंच जाए, जहां इसकी जरूरत है, यानी गरीबी हटाने को, तो दुनिया रहने लायक कहीं बेहतर हो जाए।

इसी बीच वैश्विक महामारी ने आय असमानता में और ज्यादा अंतर बनाकर निंदनीय स्तर पर पहुंचा दिया है। अमेरिका में नीति अध्ययन संस्थान ने बताया है कि महामारी के दौरान खरबपतियों की संयुक्त धन–दौलत में 44.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जबकि इस अवधि में 8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जो भी हो, अमेरिका के चोटी के 50 अमीरों के पास 16.5 करोड़ गरीबों के बराबर धन है। भारत में भी आय असमानता कम चौंकाने वाली नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे विभाग (2013) की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है और एक किसान की औसत मासिक आय महज 6,424 रुपये है जो कि गैर कृषि व्यवसाय में होने वाली आमदनी से लगभग आधी है। यही वजह है कि किसान अपने उत्पाद का न्यूनतम मूल्य तय कराकर एक निश्चित आय को सुनिश्चित बनाने के लिए आंदोलनरत है।

ऑक्सफैम की 'इन्क्युवैलिटी वायरस रिपोर्ट' का खुलासा है कि महामारी के दौरान भारत के खरबपतियों की दौलत में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। आसान भाषा में, चोटी के 11 खरबपतियों के पास आया यह धन मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कामों का अगले 10 साल तक भुगतान कर सकता है। दूसरे शब्दों में, आबादी के सिर्फ एक प्रतिशत भाग के पास निचले स्तर पर आने वाले 95.3 करोड़ लोगों के धन के बराबर है।

यह समझने के लिए कि आय में बढ़ोतरी किस प्रकार गरीब के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं तो वैश्विक प्राथमिक आय बनाने की व्यवहार्यता वाले प्रयोग को देखना होगा। कोविड महामारी से पहले, वर्ष 2018 में, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फाउंडेशन फॉर सोशल चेंज नामक परमार्थ संस्थान के साथ मिलकर वैंकूवर इलाके के 50 बेघर लोगों को 7000 डॉलर (6,206 अमेरिकी डॉलर) दिए। इस दौरान संस्थान के लोग निगरानी करते रहे कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। परिणाम न केवल चौंकाने वाले अपितु उत्साहवर्धक भी रहे। बाकी जगहों पर भी किए गए इस प्रकार के अध्ययनों में, प्रत्येक में नतीजा कमोबेश मिलता–जुलता था।

हमारे देश की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है और एक किसान की औसत मासिक आय महज 6,424 रुपये है जो कि गैर कृषि व्यवसाय में होने वाली आमदनी से लगभग आधी है।

गरीब को पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से करना नहीं आता, इस आम धारणा के विपरीत परिणामों ने स्पष्ट बता दिया कि इन लोगों ने कितनी समझदारी से उपलब्ध सीमित आर्थिक मदद का उपयोग किया है। इस पैसे का उपयोग उन्होंने जरूरत की वस्तुएं जैसे कि भोजन, कपड़े, घर और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं पाने के लिए किया। समाचार पत्र की रिपोर्ट बताती है कि जहां इन गरीबों की भोजन जरूरतों में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई वहीं नशे अथवा शराब पर 39 फीसदी की कटौती कर भरपाई की। इन बेघर लोगों ने अपने सिर पर छत का इंतजाम सबसे पहले चुना। इसलिए इस अध्ययन ने पक्के तौर पर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया भर में गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की अहमियत क्या है और इसकी प्राप्ति को किस कदर संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हाथ में इतना कम धन मुहैया करवाने पर भी यह राशि अत्यंत गरीबी की चंगुल से उबारने में मददगार है।

इसकी बजाय हम देखते हैं कि सरकारें विकास को गति देने के नाम पर कॉर्पोरेट जगत का मुनाफा बढ़ाने को कर रियायतें, आर्थिकी प्रोत्साहन पैकेज, कर्ज माफी, मदद और भारी भरकम सब्सिडी जैसी गलत नीतियों के माध्यम से पैसा खरबपतियों के खजाने में यह कहकर पहुंचा देती हैं कि काम–धंधे में इजाफा होने से यह अंततः गरीब और जरूरतमंदों के पास पहुंचेगा। जब बात गरीब को हिस्सा देने की आए तो यह तर्क दिया जाता है कि सीधा फालतू पैसा देने पर हर किसी के पास ज्यादा खरीदारी करने को धन हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति में इजाफा होगा।

अतः आर्थिक विकास का मॉडल बहुत चतुराई से आय असमानता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है और यह अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है, जबकि गरीबों से अपना गुजर–बसर खुद चलाने की उम्मीद की जाती है।❑❑

लेखक खाद्य एवं कृषि विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/the-poor-also-get-a-share-in-the-development-46282//

कोरोना इफेक्टः

आर्थिक मोर्चे पर भारत कई देशों से बेहतर

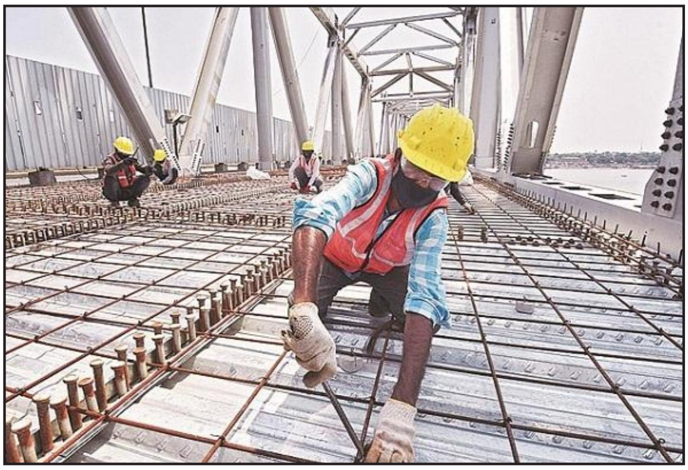

जैसे–जैसे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, वैसे–वैसे कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के मोदी सरकार पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह वैक्सीन का मामला हो या फिर आर्थिक बदहाली का, कोरोना की क्रूरता से ज्यादा विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की कथित उदासीनता और अक्षमता को समस्या के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं।

अपनी कुंद राजनीतिक धार को तेज करने का उनको यह उचित अवसर लग रहा है। जब लोग परेशान हो, आर्थिक रूप से तंगहाल हो और जवाबदेही थोपने के लिए किसी को ढूंढ रहे हों, तो पहली फायर लाइन में सरकारें आती ही हैं। लेकिन जिस तरह चिंगारी को पेट्रोल सुंधाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, वह केवल आगे की राजनीति की राह तय नहीं करेगी, बल्कि भारत का भविष्य भी प्रभावित होगा। जाहिर है, सत्ता के सिंहासन से अलग हुई कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु देश के नागरिक के रूप में सच्चाई जानने या बताने का दायित्व देश के प्रति सद्भावना रखने वाले का बनता है।

देश को यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार अभी भी बहुत मजबूत है। कोरोना से पार पाने के बाद जिन चंद देशों में तेज आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया है, उसमें भारत भी है। और यह अनुमान हवा में नहीं है, इसके ठोस आधार हैं।

– विक्रम उपाध्याय

जनवरी 2020 में भारत में कोरोना का असर सामने आने लगा। मार्च के खत्म होते–होते देश में संपूर्ण लॉक डाउन लग गया। जो मध्य सितंबर तक चला। लगभग 7 महीने भारत में व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियां ठप्प सी रहीं। इस बीच आकड़ा आया कि भारत की अर्थव्यवस्था में 23 फीसदी से अधिक का संकुचन आ गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2020–21 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के लिए जीडीपी के अनुमान जारी करते हुए बताया कि अभी भी भारत का कुल जीडीपी 33.14 लाख करोड का है, जबकि 2019–20 की दूसरी तिमाही में यह 35.84 लाख करोड़ रुपये का था। यानी इसमें 7.5 प्रतिशत का संकुचन दिखा।

भारत की जीडीपी में इतनी गिरावट क्यों आई उसे समझने के लिए डब्लूटीओ की यह रिपोर्ट पढ़े, जिसमें कहा गया है कि 2020–21 की पहली तिमाही में वैश्विक सेवाओं का निर्यात वर्ष–दर–वर्ष 7.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत तक कम हुआ। उसमें भी एशिया क्षेत्र में सेवा निर्यात में 16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हम सबको मालूम है कि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 54.77 फीसदी है। यानी सर्विस सेक्टर के बैठने का पूरा असर भारत के जीडीपी पर पड़ा।

अब आप इस अवधि में विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं का हाल देखें। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिंच ने सितंबर 2020 में यह अनुमान जारी किया कि वैश्विक जीडीपी में कोरोना के कारण 2020–21 में 4.4 फीसदी की कमी आएगी।

सितंबर में जब यह आकड़ा आया कि भारत की जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई है, तो उस समय दुनिया के कई देशों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई थी। तब स्पेन की जीडीपी में 22.1, ब्रिटेन की जीडीपी में 21.7, फ्रांस की जीडीपी में 18.9, इटली

की जीडीपी में 17.7 और कनाडा की जीडपी में 13 फीसदी का संकुचन हुआ था। वहां तो कोई चिल पौ नहीं मचाई किसी ने। अपने को आर्थिक सुपर पावर कहने वाले और भारत की जीडपी के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका की जीडीपी में 9.9 फीसदी का, रूस की जीडीपी में 9.1 फीसदी का और जापान की जीडपी में 9.9 फीसदी का सिकुड़न देखा गया। केवल चीन ही एकमात्र देश था जिसने यह दावा कि कोरोना में भी उसकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक रही और उसने 3.2 फीसदी की वृद्धि हासिल की। चीन के आकड़े पर सभी लोगों को हैरत हुई और उसे कई देशों ने मैनिपुलेटिव करार दिया।

सितंबर में लॉकडाउन खत्म हो गया और फिर से आर्थिक गतिविधियां चल पड़ी। फिर से विश्व भर की अर्थव्यवस्था के नए अनुमान सामने आने लगे। 2020–21 की अंतिम तिमाही तक भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी थी। फरवरी 2021 में मूडीज एनालिटिक्स ने यह अनुमान जारी किया कि 2021 में भारती जीडीपी 12 फीसदी तक बढ़ सकती है। यही नहीं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 12.6 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जो कि जी–20 देशों में सबसे अधिक है। मूडीज ने अप्रैल में जारी अपने अनुमान में भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि संक्रमण की मौजूदा लहर से निपटने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह वैसा नहीं है जैसा पिछले साल देशव्यापी तालाबंदी के समय था, इसलिए भारत की आर्थिक गतिविधियों पर 2020 की तुलना में कम गंभीर प्रभाव होगा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भारत की जीडीपी में दोहरे अंकों की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। जिसके अनुसार भारत वित्त वर्ष 2021 में 13.7 फीसदी की वृद्धि हासिल कर सकता है।

कांग्रेस कहती है कि मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को डूबा दिया। कांग्रेस के अनुसार इतना भी पैसा नहीं है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगा दिया जाए। अपने इसी वक्तव्य को सही मानते हुए, वह कभी सेंट्रल विस्टा के निर्माण को रोकना चाहती है, जिस पर 13 हजार करोड़ खर्च होने है तो कभी कहती है कि सरकार लोगों महंगाई और टैक्स के जरिए लोगों का खून चूस रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि मोदी ने देश को कर्ज में डूबो दिया है और अब हमें राहत के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है। आकड़े क्या कहते हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार पिछले साल 19.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर विभिन्न देशों ने कर्ज लिए। इसमें से अकेले अमेरिका 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया, जो 2008 की महामंदी समय लिए गए कर्ज से भी ज्यादा है। यह राशि लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के आकार से भी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार जी–7 समूह के देशों ने पिछले साल अपनी जीडपी के औसत 85 फीसदी के बराबर कर्ज को बढा़कर अब 140 फीसदी कर लिया है। जबकि भारत का कुल कर्ज जो वर्ष 2019–20 में जीडीपी का 74 फीसदी था, उसे बढ़ाकर 90 फीसदी कर लिया है। उसमें भी हमारा विदेशी कर्ज कुल जीडीपी का 11 फीसदी है, जो चीन के बराबर है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस पर विदेशी कर्ज उनकी जीडीपी से भी ज्यादा है। आईएमएफ ने भारत के इस कर्ज को मैनेजिबल और विकास में सहायक बताया है। आईएमएफ के अनुसार भारत जल्दी ही अपने कर्ज को जीडीपी के 80 फीसदी तक ले आ सकता है।

देश को यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार अभी भी बहुत मजबूत है। कोरोना से पार पाने के बाद जिन चंद देशों में तेज आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया है, उसमें भारत भी है। और यह अनुमान हवा में नहीं है, इसके ठोस आधार हैं। मसलन कोरोना और लॉक डाउन के बावजूद 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत की विकास दर नकारात्मक से सकारात्मक हो गई, इस साल 1.6 फीसदी की वृद्धि दर हासिल की गई। बेरोजगारी में बढ़ोतरी की दर 6.5 फीसदी है। इसकी तुलना अन्य बड़े देशों से करें तो ब्राजील में बेरोजगारी दर 11.93 फीसदी है। इटली में 9.88 फीसदी है। फ्रांस में 8.12 फीसदी है और अमेरिका मे लगभग 4 फीसदी है। भारत में ब्याज दर 5 फीसदी से कम है और देश में विदेशी मुद्रा का भंडार 597 अरब डॉलर के बराबर है। कोविड के बावजूद भारत में 2020–21 में 89.72 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया जो पिछले साल से 10 प्रतिशत अधिक था।

असाधारण हालत में कोई भी साधारण परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा देश है, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अब नए सिरे से अर्थव्यवस्था के निर्माण पर लगना पड़ेगा। इसके लिए प्रोत्साहन के साथ साथ उद्यमियों में उत्साह का भी संचार करना पड़ेगा। यह दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं है। पूरे राजनीतिक सिस्टम का है, क्योंकि यहां सिर्फ मोदी नहीं हैं। विपक्षी पार्टियां भी कई राज्यों में सरकारे चला रही हैं। वहां भी नई उर्जा की जरूरत पड़ेगी। वहां भी बिजनेस कांफिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। झूठे और मनगढंत आकड़ों से किसी का भला नहीं होगा। यह सबको सोंचना चाहिए। ❑❑

कोविड काल में छोटे उद्योगों का कठिन सफर

वैश्विक सलाहकारी कम्पनी मैकेंजी ने अक्तूबर 2020 के एक अध्ययन में कहा था कि यूरोप के छोटे उद्योगों का स्वयं का अनुमान है कि आधे आने वाले 12 माह में बंद हो जायेंगे। भारत की परिस्थिति ज्यादा दुष्कर है क्योंकि हमारे छोटे उद्योगों ने लाकडाउन के साथ साथ नोटबंदी और जीएसटी की मार भी खाई है। ई–कॉमर्स और बड़ी कंपनियों ने छोटे उद्योगों के बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है। अतः प्रश्न उठता है कि छोटे उद्योगों को जीवित रखा ही क्यों जाए? उन्हें मर क्यों न जाने दिया जाये? यदि बड़े उद्योग माल को कम कीमत में उत्पादन कर सकते हैं तो उसे छोटे उद्योगों से उत्पादन करने से लाभ क्या है?

विषय यह है कि छोटे उद्योग यद्यपि माल महंगा बनाते हैं परन्तु वे हमारे भविष्य के उद्यमियों के इनक्यूबेटर अथवा लेबोरेटरी भी हैं। आज का छोटा उद्यमी कल बड़ा हो सकता है। धीरुभाई अम्बानी किसी समय छोटे उद्यमी थे। यदि उनके छोटे उद्योग को पनपने का अवसर नहीं मिलता तो वे कभी बड़े भी नहीं होते। साथ ही ये भारी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं। रोजगार उत्पन्न होने से जनता की सृजनात्मक क्षमता उत्पादक कार्यों समाहित हो जाती है। यदि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो वे अंततः अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे जो हो भी रहा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो उनके एमए पढ़े छात्र भी अब एटीएम तोड़ने जैसे कार्यों में लिप्त हो गये हैं चूँकि वे बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में लोगों के अपराध में लिप्त होने से सुरक्षा का खर्च बढ़ता है, देश पर पुलिस का खर्च बढ़ता है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना विकसित होती है और सामाजिक और पारिवारिक ढांचा विघटित होता है। देश में असुरक्षित वातावरण के कारण विदेशी कम्पनियां भी निवेश करने से कतराती हैं। इसलिए यदि हम छोटे उद्योगों से बने माल के ऊँचे दाम को सहन करें तो इस भार के बावजूद आर्थिक विकास हासिल होता है चूँकि

छोटे उद्योगों को जीवित रखने के लिए हमें पहला कार्य यह करना होगा कि उनकी उत्पादन लागत कम आये। इसके लिए ऋण देने के अतिरिक्त ठोस कदम उठाने होंगे।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

अपराध कम होते है और सामाजिक वातावरण आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश के अनुकूल स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम बड़े उद्योगों से उत्पादन कराएं तो बेरोजगारी और अपराध दोनों बढ़ते हैं। यद्यपि बाजार में सस्ता माल उपलब्ध होता है परन्तु अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है क्योंकि अपराध बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारों को न्यूनतम सुरक्षा देने को मनरेगा जैसे कार्यक्रमों पर सरकार को खर्च भी अधिक करना पड़ता है। मेरा आकलन है कि मनारेगा पर खर्च की गयी रकम मूल रुप से उनुत्पादक कार्यों में लगती है। वही रकम यदि छोटे उद्योगों को समर्थन में लगायी जाये तो उत्पादन बढेगा। अतएवं केवल बड़े उद्योगों के सहारे आर्थिक विकास की नीति विफल होने की संभावना ज्यादा है। पिछले 6 वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर गिरने यह एक बड़ा कारण दिखता है।

छोटे उद्योगों को जीवित रखने के लिए हमें पहला कार्य यह करना होगा कि उनकी उत्पादन लागत कम आये। इसके लिए ऋण देने के अतिरिक्त ठोस कदम उठाने होंगे। यूरोपीय यूनियन की छोटे उद्योगों की गाइड बुक में सुझाव दिया गया है कि छोटे उद्योगों को ट्रेनिंग, रिसर्च एवं सूचना उपलब्ध करने के लिए उनके गुट अथवा क्लस्टर बनाने चाहिए और इन क्लस्टरों का संचालन छोटे उद्योगों के अपने संगठनों के हाथ में दे देना चाहिए। जैसे वाराणसी में यदि बुनकरों को समर्थन देना है तो वाराणसी के बुनकरों के संगठन के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग, रिसर्च और सूचना उपलब्ध कराई जाए। उनके संगठन को सही ज्ञान होता है कि किस प्रकार की तकनीक की जरूरत है और किस प्रकार की ट्रेनिंग कामयाब होगी। यदि यही कार्य किसी एनजीओ अथवा किसी सरकारी तंत्र के माध्यम से कराया जाता है तो उन्हें जमीनी स्थिति का ज्ञान नहीं होता है और उनके द्वारा चलाए गये कार्यक्रम वैसे होते हैं जैसे तेल पर पानी के रंग बिखरते हैं। तमाम एनजीओ ऐसी योजनाओं में अपनी रोटी सेक रहे हैं। चिकने पन्नो पर रपटें लिखी जाती हैं लेकिन छोटे उद्योग मरते ही जाते हैं। इस दिशा में भारत सरकार की नीति विपरीत दिशा में दिख रही है। छोटे उद्योगों के परिसंघ के सचिव अनिल भारद्वाज के अनुसार सरकार द्वारा छोटे उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो बोर्ड बनाये गये हैं उसमें पूर्व में छोटे उद्योगों के संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान दिया जाता था। बीते दिनों में सरकार ने इन बोर्ड में केवल अधिकारी और नेताओं की नियुक्ति की है और छोटे उद्योगों के संगठनों की सदस्यता पूर्णतया समाप्त कर दी है। यानी जिसके हित के लिए ये बोर्ड बनाये गये हैं वे ही इन बोर्डों में अनुपस्थित हैं। इस नीति को बदलना चाहिए।

मनारेगा पर खर्च की गयी रकम मूल रुप से उनुत्पादक कार्यों में लगती है। वही रकम यदि छोटे उद्योगों को समर्थन में लगायी जाये तो उत्पादन बढेगा। अतएवं केवल बड़े उद्योगों के सहारे आर्थिक विकास की नीति विफल होने की संभावना ज्यादा है।

दूसरा काम सरकार को छोटे उद्योगों को इस कठिन समय में वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार की नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के अप्रैल 2020 के एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड में छोटे उद्योगों द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन का एक अंश कुछ समय के लिए सब्सीडी के रूप में दिया गया है जिससे कि छोटे उद्योग भी जीवित रहें और और उनमें कार्यरत श्रमिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यहाँ भी भारत सरकार की नीति विपरीत दिशा में है। सरकार ने छोटे उद्योगों को सरल ऋण उपलब्ध करने पर जोर दिया है जो कि सामान्य परिस्थितियों में सही बैठता। लेकिन जिस समय छोटे उद्योगों द्वारा बनाया गया माल बाजार में बिक ही नहीं रहा है उस समय उनके द्वारा ऋण लेकर कठिन समय पार करने के बाद उनके ऊपर ऋण का अतरिक्त बोझ आ पड़ेगा और वे ऋण के बोझ से उबर ही नहीं पायेंगे। यूँ ही मरने के स्थान पर वे ऋण के बोझ से दब कर मरेंगे। इसलिए ऋण पर सब्सीडी देने के स्थान पर उसी रकम को सीधे नगद सब्सीडी के रूप में देना चाहिए।

छोटे उद्योगों द्वारा अकसर आयातित कच्चे माल का उपयोग करके माल तैयार किया जाता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है अथवा निर्यात किया जाता है। इनमें से एक कच्चा माल प्लास्टिक है। सरकार ने प्लास्टिक पर आयात कर बढ़ा दिए हैं जिसके कारण कच्ची प्लास्टिक का दाम अपने देश में बढ़ गया है और विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक का माल बनाने वाले छोटे उद्योग बंद प्राय हो गए हैं। यही परिस्तिथि अन्य कच्चे माल की हो सकती है। ऐसे कच्चे माल पर आयात कर घटना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करके छोटे उद्योगों को राहत पंहुचाना चाहिए अन्यथा न तो भविष्य में धीरुभाई जैसे उद्यमी बनेगे न ही आर्थिक विकास हासिल होगा। ❑❑

महामारी से लड़ने में प्रभावी होगा वन नेशन, वन हेल्थ सिस्टम

भारत में जबसे कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ है, तभी से भारत में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की नीति को अपनाकर देश में स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसा बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि देश की केन्द्र व राज्य सरकारें कोरोना जैसी महामारी के समय तथा उसके उपरान्त व किसी भी महामारी से देशवासियों की रक्षा करने में सक्षम साबित हो सके तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बना रहे। चूंकि स्वास्थ्य को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है जिससे नोडल एजेंसियां तो राज्यों के नियन्त्रण में ही होती है जिससे राज्य सरकार अपनी जबाबदेही और प्राथमिकता को साबित कर सकने में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाती है।

विश्व में कोरोना जिस तेजी से फैला उससे आर्थिक रुप से सम्पन्न देशों की अर्थव्यवस्था भी ड़ावांड़ोल हो गई। इसी प्रकार भारत को भी भारी आर्थिक, सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा है। भारत में 77 वर्ष से स्वास्थ्य का ढ़ांचा इस प्रकार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और मेड़िकल कॉलेज स्तर का है। परन्तु कोरोना के आक्रमण से यह ढ़ांचा लगभग धाराशाही हो गया है तथा इसे इन परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं ठहराया जा सकता है। भारत के सर्वजन आरोग्य के कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भारत में 1950 से 2014 तक प्रतिवर्ष औसत गति से छः मेड़िकल कालेजों की स्थापना हुई जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभी तक अपने कार्यकाल में 145 नए मेड़िकल कॉलेजों की स्थापना की है। अर्थात 29 मेड़िकल कालेज प्रतिवर्ष स्थापित हो रहे है। 2014 में सभी मेड़िकल कॉलेजों में 53,348 सीटें थी जो अब बढ़कर 84,649 हो गई है। 2014 में पीजी में सीटों की संख्या 23 हजार थी जो बढ़कर 44 हजार हो गई है। 2025 तक 16 नए एम्स श्रेणी के कॉलेज भी प्रारम्भ हो जायेंगे। कॉलेजों में बुनियादी ढ़ांचा मजबूत किया जा रहा है तथा फैकल्टी का प्रबंध किया जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एमएनसी) की ओर से एक नया कानून लाया गया है। कोशिश यह है कि प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल की स्थापना हो जाये।

वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की नीति इस प्रकार से बननी चाहिए कि केन्द्र व राज्य सरकारों में आपसी टकराव दूर हो सके। विभिन्न चिकित्सकीय विभाग एकीकत की राह में चल सके जिससे लालफीताशाही दूर हो सके।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

देश में होम्योपैथी, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी चलन में है तथा नर्सिंग तथा पैरा मेड़िकल सुविधाओं का स्थापना होनी चाहिए। देश में इन सब को मिलाकर एक नेशनल हेल्थ सिस्टम की शुरुआत होने से ही वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम का सपना पूरा करना होना। देश की केन्द्र सरकार को चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार भी पीजी स्पेशल पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक जिले में पीजी सीट वाले मेड़िकल कालेज खेलने की आवश्यकता है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में 25 प्रतिशत लोगों को मेडिकल क्षेत्र में रोजगार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से मिलता है। जबकि भारत में मात्र 10 प्रतिशत लोग ही रोजगार पाते है। मेड़िकल क्षेत्र में रोजगार का कोई व्यवस्थित तंत्र देश में विकसित नहीं पाया है। मात्र ड़ाक्टर, अस्पताल व मेड़िकल स्टोर ही विनियमित किये हुए है और कुछ भी विनियमित नहीं है। मेड़िकल शिक्षा को बुनियादी शिक्षण से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

इस समय पैरामेडिकल एवम् नर्सिंग क्षेत्र में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर चिकित्सालयों में तैनात किया जा सकता है। दूसरी तरफ देश के प्रत्येक व्यक्ति को सेहत मन्द रहने के विभिन्न गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। देश में विभिन्न सरकारी विभाग जैसे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, पोषण (महिला तथा बाल विकास), समाज कल्याण इत्यादि को समाहित करके स्वास्थ्य विभाग के दायरें को बढ़ाया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य के विचार को आरम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि जागरुकता आरोग्य का कारक बनकर व्यवस्था के बोझ को कम कर सके।

सरकारों को स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक की मेड़िकल कालेजों में फैकल्टी की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती है। मेड़िकल क्षेत्र में अफसरशाही भी बड़ी मात्रा में देखी जाती है। कोरोना के इस संकट को अवसर में बदलना चाहिए। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की नीति इस प्रकार से बननी चाहिए कि केन्द्र व राज्य सरकारों में आपसी टकराव दूर हो सके। विभिन्न चिकित्सकीय विभाग एकीकृत की राह में चल सके जिससे लालफीताशाही दूर हो सके। बस आवश्यकता कि चिकित्सीय सुविधाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर देश में एक स्वस्थ्य बुनियादी संरचना पूर्नगठित की जा सके। संकट की घड़ी में खतरें के बीच स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा पत्रकार एक योद्धा के रुप में जंग लड़ रहे है। इनमें जज्बा तो है परन्तु मजबूरी ज्यादा महसूस की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ सावधानी ही बचाव है। जनसाधारण अपनी जिम्मेदारी समझे तथा सरकार की गाइड़ लाइन का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ्य रहने के लिए प्रयास करने ही होंगे तभी सभी देशवासियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षो से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

अंकों के खेल से बाहर निकलने का समय

देश के प्रायः सभी राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को लेकर शोर भी अब थमने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे चीखते, चिल्लाते और दम तोड़ते मरीजों पर अब फोकस करने के बजाए महामारी से प्रभावित दूसरे आयामों की ओर रुख कर रहे हैं। अखबारों में भी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की चिताओं की वीभत्स तस्वीरें अब नहीं छप रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी ने भारत के संपेरो के देश वाली छवि को दुनियां के सामने फिर से प्रतिस्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अकेले बीबीसी ने ही 250 से अधिक भारत विरोधी रिपोर्टें प्रकाशित और प्रसारित की हैं।

अभी तीसरे लहर के आने को लेकर संभावनाएं प्रकट की जा रही है, किंतु इसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, किंतु इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। यह भी सिर्फ अनुमान पर आधारित है। हम यहां कोरोना संकट से हुए जानमाल के नुकसान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य पर इस महामारी ने जो असर डाला है, उसे लेकर चिंतित हैं। यह विषय मीडिया के लिए टीआरपी बढ़ाने वाला नहीं हो सकता, लिहाजा इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई है। समाचार माध्यमों ने सिर्फ हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के निरस्त होने की खबरें प्रमुखता से छापी हैं और चैनलों पर दिखाई हैं। औपचारिकता के लिए कुछ चर्चा–परिचर्चा भी देखने सुनने को मिली, किंतु उससे शिक्षक और विद्यार्थी गायब दिखे। संभव है, उन्हें इसके लिए उपयुक्त नहीं समझा गया होगा। चैनलों में देखने को मिला कि पैनल में कुछ ऐसे महानुभाव नजर आए, जो शिक्षा को कारपोरेट सेक्टर की भांति चलाने में विश्वास रखते हैं। इनके लिए फैक्ट्री सरीखे शिक्षण संस्थानों में छात्र और शिक्षक एक 'रॉ मैटेरियल' से अधिक अहमियत नहीं रखते हैं, जिनकी न तो अपनी कोई सोच होती है और न हीं समाज को देने के लिए अपना कोई चिंत्तन।

लंबे अरसे से शिक्षक और विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की प्रचलित व्यवस्था तथा मूल्यांकन की पद्धति को बदलने की आवश्यकता महसूस करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के मूल्यांकन के बेहतरीन सुझाव भी दिए गए हैं, जिनका क्रियान्वयन शेष है।

– **निरंजन सिंह**

देश में स्कूली शिक्षा को संचालित करने वाले छह दर्जन से अधिक बोर्ड हैं, जिनमें से भेंड़ चाल चलने के आदि रहे अधिकांश ने सीबीएसई के तर्ज पर अपनी बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। इनमें यूपी बोर्ड भी है, जो दुनियां की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था मानी जाती है। हाल के वर्षों में इस बोर्ड को उत्तर प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा कराने का श्रेय भी जाता है, किंतु पाठ्यक्रम, परीक्षा और आधुनिक तरीके से शिक्षा देने के मामले में यह आज भी सीबीएसई का नकल करने से पीछे नहीं है।

प्रायः सभी बोर्डों के परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद इस बात पर चर्चा हो रही है कि अब परीक्षाफल कैसे तैयार किया जाए। उत्तर भारत के गावों में 'भोज के दिन कोहड़ा रोपने' की एक प्रचलित कहावत है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ हो रही है। कहने के लिए परीक्षा संस्थाएं एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि सरकारें राजनीतिक निहितार्थ के लिए भी इन संस्थाओं का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। परीक्षाओं के निरस्त होने के संदर्भ में भी इसे देखा जा सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा निरस्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री क्यों करते हैं और इसका निर्णय कैबिनेट क्यों लेता है? या फिर राज्यों में परीक्षा निरस्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री अथवा संबंधित शिक्षा मंत्री द्वारा क्यों की जाती है? क्या परीक्षा

संस्थाओं के निर्णय लेने की स्वायतता का यह मज़ाक नहीं है? यदि सरकारें परीक्षा निरस्त करने का निर्णय ले सकती हैं, तो फिर परिणाम घोषित करने का मानक भी कैबिनेट को ही तय करना चाहिए। सच्चाई यह है कि करोड़ों बच्चों के हित से जुड़े इतने गंभीर विषय पर शिक्षाविदों और शिक्षकों की राय लेने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक दबाव में और आनन–फानन में निर्णय ले लेते हैं, जिन्हें आगे का रास्ता पता नहीं होता, कि परिणाम कैसा होगा? केंद्र और राज्यों में परीक्षाएं निरस्त होने के पश्चात परिणाम को लेकर प्रायः विशेषज्ञों की समितियां गठित की जा रही हैं, जिनसे तीन दिन से लेकर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा जा रहा है। कोरोना संकट के इस भयावह दौर में मानसिक तनाव झेल रहे देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ यह मजाक नहीं तो और क्या है? बेहतर होता कि जब परीक्षाएं कराने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी, उसी समय राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर परीक्षाएं निरस्त करने और परीक्षाफल तैयार करने के लिए एक सर्वमान्य मानक तैयार करने के हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित की जाती तथा स्कूल स्तर से शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ–साथ अभिभावकों के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते, तत्पश्चात ऐसा कोई निर्णय निकल कर आता, जिसकी घोषणा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए थी। वर्तमान में आनन–फानन में लिया जाने वाला निर्णय घातक हो सकता है।

लंबे अरसे से शिक्षक और विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की प्रचलित व्यवस्था तथा मूल्यांकन की पद्धति को बदलने की आवश्यकता महसूस करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के मूल्यांकन के बेहतरीन सुझाव भी दिए गए हैं, जिनका क्रियान्वयन शेष है। इस बात से शायद ही कोई सहमत हो कि सिर्फ हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाफल के आधार पर किसी छात्र को हमें मेधावी मान लेना चाहिए। अंकों के इस खेल ने माध्यमिक शिक्षा को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। कोई विद्यार्थी मेधावी है, यह मान लेने के लिए सिर्फ उसका एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर की तार्किक, विश्लेषण, शोधपरक ज्ञान, शारीरिक दक्षता और चारित्रिक गुणों का सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समाज के प्रति उसकी संवेदना और राष्ट्रीयता की भावना सहित अन्य मानकों को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन की प्रचलित पद्धति से बाहर निकलने की बात कही गई है।

सतत, समग्र और तार्किक मूल्यांकन की व्यवस्था को अमल में लाने से पहले हमें शिक्षा व्यवस्था को भी और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। वास्तविकता के धरातल पर देखें तो अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं, जिन्हें भरने का प्रयास सरकारों द्वारा गंभीरतापूर्वक नहीं किया जाता। बुनियादी सुविधाओं का रोना अलग है। दशकों से शिक्षण सहित अन्य मद में लिए जानेवाले शुल्कों में नहीं के बराबर वृद्धि के चलते बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। भवन से लेकर फर्नीचर तथा पुस्तकालय से लेकर प्रयोगशाला तक में जरूरी सामग्री मौजूद नहीं है। स्कूलों में खेल के मैदान या तो है ही नहीं या फिर प्रबंध तंत्रों द्वारा उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में हम सतत और समग्र मूल्यांकन की बात आखिरकार कैसे कर सकते हैं।

आज जब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम तैयार करने की बात सामने आ रही है, तो बोर्ड के अधिकारी और विशेषज्ञ इस उधेड़ बुन में हैं कि आखिरकार पूर्व की किन परीक्षाओं पर भरोसा किया जाए। संदेह के दायरे में पूर्व की परीक्षाओं के सिर्फ अंक नहीं हैं, बल्कि उन अंकों के प्रदाता शिक्षक भी हैं, जिन पर न तो आज का 'सिस्टम' और न हीं समाज भरोसा करने को तैयार है। यह समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा कि किन परिस्थितियों में आज का शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर रहा है। शिक्षक और छात्र का मानक कहीं भी सम्यक रूप से देखने को नहीं मिलेगा। राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों को यदि छोड़ दें तो वित्तविहीन स्कूलों की दशा अत्यंत दयनीय हैं। जब उत्तर प्रदेश में ठेके पर नकल होता था उस समय हजारों की संख्या में वित्त विहीन स्कूल अस्तित्व में आए, जो मानक पर किसी भी तरह से खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता ही संदेह के घेरे में रहती है, जिनसे मूल्यांकन की शुचिता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बावजूद इसके हमें संकट के दौर में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस समय मूल्यांकन का सटीक पैमाना हाईस्कूल के लिए यही हो सकता है कि कक्षा नौ की वार्षिक परीक्षा, कक्षा दस के मासिक टेस्ट तथा प्री बोर्ड की परीक्षा के अंकों का औसत निकालकर अंतिम परिणाम तैयार किए जाएं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के लिए हाईस्कूल परीक्षा के अंक, ग्यारहवीं वार्षिक परीक्षा तथा बारहवीं प्री बोर्ड के अंकों का औसत निकालकर परिणाम तैयार किए जाएं। इससे छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, किंतु यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि परीक्षाफल तैयार करने का मानक सभी बोर्डों का एक जैसा हो, ताकि अंकों का ग्राफ ज्यादा ऊपर नीचे न हो सके, क्योंकि कुछ राज्य अपने विद्यार्थियों को अधिक लाभ देने के लिए अंकों का खेल, खेल सकते हैं। ❑❑

(लेखक रामगोपाल त्रिपाठी इंटर कालेज विजयीपुर फतेहपुर में प्रिंसिपल हैं।)

नयी स्वास्थ्य क्रांति की दरकार

कोरोना वायरस के कहर से पिछले महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हज़ारों लोगों की जान चली गई। लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन–सहन भी एकदम बदल गया है। यह वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सबकुछ उलट–पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुई, जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख़्त पाबंदी लगानी पड़ी, लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए हैं। ये सारे क़दम इसलिए उठाए गए हैं, ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके।

कोरोना वायरस (सीओवी) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। डब्लूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार ने भारत के कई हिस्सों में स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया था। मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच सरकारी और निजी अस्पतालों में मूल भूत सुविधाओं का हाहाकार मचा है। इस संकट के समय में भय, व्याकुलता, घबराहट हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रहे है। हलाकि इन सबके बीच प्रश्न है कि क्या संकट को समझने और इससे निपटने में हमसे भी कोई चूक हुई है। जाहिर है इस स्थिति में काम चलाऊ नीति के बजाय भारत में एक नयी "स्वस्थ क्रांति" की दरकार है, जिसके विभिन्न आवश्यक पहलूँ हैं

इस स्वास्थ्य क्रांति का सर्वप्रथम पहलू है– स्वस्थ सुधार कार्यक्रम की व्यापकता और लोक नीति में उसकी प्राथमिता राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और नीति आयोग की रिपोर्ट (2018),

जरुरी है कि हम इस राष्ट्रीय आपदा से सीख ले, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर, भारत में नयी स्वास्थ्य क्रांति को दिशा दे। सही मायने में तभी हम सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यही इस संकट में हुई मानव जीवन के नुकसान को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

– अभिषेक प्रताप सिंह

जिसमें चार चैप्टर्स केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित थे, दोनों ने भारत में स्वास्थ्य सुधार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी।

इन रिपोटर्स के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय बहुत व्यापक है, जिसमें कई कारक महत्वपूर्ण है जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार, निवारक और उपचारात्मत सेवाओं का अंतर, मेडिकल शिक्षा और डॉक्टर्स की संख्या, सक्षम नर्सिंग और स्वास्थकर्मी, नयी स्वास्थ्य तकनीक और शोध, लैब का विस्तारीकरण के साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर में सरकारी खर्चा को बढ़ावा देना। ये सब कारक एक कड़ी के सामान हैं, जिनकी बेहतर स्थिति व्यापक स्वास्थ्य सुधार की पहली शर्त है।

इसका दूसरा पहलू स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर हो रहे खर्च से जुड़ा है। हम अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार के 2.5 प्रतिशत और राज्य बजट के 8 प्रतिशत खर्च के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। धन अभाव में ये पूरी व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य पर बड़े निजी निवेश ने इसे मानव कल्याण से इतर, महंगा और लाभ केंद्रित बना दिया है। इसलिए सबसे पहले जरुरी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च को बढ़ावा देना।

तीसरा पहलू है– स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एक बड़ी चिंता है। लगभग 80 प्रतिशत कोरोना के मरीज 'बेहतर प्राथमिक परामर्श' को तरसते रहे। इसलिए जरूरी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों की तादाद को बढ़ाया जाए। आज थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश हमारे सामने उदाहरण है। जिन्होंने एक सशक्त और सक्षम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था के आधार पर कोरना पर लगभग विजय प्राप्त कर ली।

चौथी बात, भारत जैसे विशाल देश में 'स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण' की आवशयकता से है। किसी भी आपदा के समय में नजदीकी क्लीनिक और पड़ोसी उपचार केंद्रों की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल पर दबाव अधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये केंद्र कम से कम शुरुआती परामर्श, दवा की उपलभ्धता और वैक्सीन अदि की उपलब्धता के लिहाज से इनकी भूमिका बढ़ी है, इसलिए इस नेटवर्क को ग्रामीण और शहरी स्तर पर मज़बूत किया जाना चाहिए।

2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख अंग पूरे भारत में हेल्थ और वैलनेस (HWC) सेंटर को मजबूत करना है। उसके अनुसार दिसंबर 2022 तक लगभग डेढ़ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इनके साथ मिलाकर अपग्रेड करना है। यह एक दूरगामी लक्ष्य है और सरकार को इस ओर तेजी दिखानी चाहिए।

पांचवा पहलू यह है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एक टीम वर्क हैं, जिसमें स्वास्थ्य और गैर स्वास्थ्यकर्मी दोनों की भूमिका होती है। आज बड़ी संख्या में दवाई, वैक्सीन लगाने, हॉस्पिटल एडमिशन से लेकर आईसीयू मॉनिटरिंग तक डॉक्टर्स के अलावा नर्स, स्पॉट बॉय, लैब तकनीशियन, लोकल फार्मसिस्ट आदि सभी अपनी भूमिका निभा रहे है। जरूरी है कि भारत अपने स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम में इन फ्रंटलाइन वर्कर की बेहतर ट्रेनिग, संख्या और सुविधा पर बल दे, जोकि किसी आपदा के समय एक स्वास्थ्य सेवाओं को तत्परता बनाये रखें। कैग (CAG) की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार, झारखंड, मप्र, उप्र, सिक्किम, उत्तराखंड और बंगाल के स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 50 फीसद पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी है। जाहिर है कि न केवल डॉक्टरों की उपलब्धता, बल्कि सहायक सेवाकार्मिकों के मोर्चे पर भी भारत में दीर्घकालिक और मानक रणनीति की आवश्यकता है।

जरुरी है कि हम इस राष्ट्रीय आपदा से सीख ले, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर, भारत में नयी स्वास्थ्य क्रांति को दिशा दे। सही मायने में तभी हम सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यही इस संकट में हुई मानव जीवन के नुकसान को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ❑❑

लेखक देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है विदेशी सोशल मीडिया

सरकार और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी ट्विटर के बीच तनातनी बढ़ गई है। हालांकि संसद की उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय समिति ने गत दिनों कंपनी के नुमाइंदों को तलब कर स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि देश का कानून सर्वोपरि है, किसी कंपनी के खुद की नीति नहीं। लेकिन गुस्ताख मल्टीनेशनल कंपनी ट्विटर ने यह कहकर कि हम अपनी खुद की नीतियों का पालन करते हैं, मामले में तनाव को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की है।

यह पहला मौका नहीं है जब कोई विदेशी कंपनी अपने पांव पसारने के चक्कर में किसी देश की संप्रभुता को चुपके से चुनौती देने और अपना विस्तार बढ़ाने की कोशिश की हो। इसे और ठीक से समझने के लिए हमें लगभग 450 साल पहले के इतिहास की ओर लौट कर देखना चाहिए। ईस्वी सन् 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज बहादुर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबारी साम्राज्य बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। अंग्रेजों ने कंपनी को असीमित अधिकार देते हुए भारत पर कब्जा जमाने का ब्लूप्रिंट भी दिया था। प्रारंभ में कंपनी एशियाई देशों में केवल कारोबार की बात करती थी, लेकिन उसका गुप्त इरादा मुख्य रूप से भारत को कब्जे में करने का था। तब का भारतीय समाज विदेशी कंपनी के गुप्त इरादों को भांप नहीं पाया, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करते–करते भारत देश में सरकार बनाने की साजिश तक में कामयाब हो गई थी। कंपनी की साजिश को साकार करने वालों में कुछ गिने–चुने हिंदुस्तानियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों की नकल करने और उनके सामानों पर फिदा कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो कंपनी का उत्पाद बढ़–चढ़कर खरीदते थे तथा खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। छह ऋतुओं और 27 नक्षत्रों वाले वैभवशाली विरासत वाले भारत देश में खुद को चौबीसों घंटे टाई सूट और हैट में नाथकर खुद को श्रेष्ठ बताने का मिथ्या बोध भी करते थे। यही वह गिने–चुने लोग थे जो कंपनी का बनाया कपड़ा पहनते थे, कंपनी की चाय पीते थे और कंपनी का खुलकर इश्तहार भी करते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए अब विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि व्यापार करने के नाम पर भारत में आ धमकी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिंसन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ''आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की तुलना 425 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही की जानी चाहिए, क्योंकि हाल के वर्षों में आई मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों की

इंटरनेट मीडिया को रास्ते पर आने की हिदायत देते हुए केंद्र की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय कंपनियां भारत के कानून का पालन करें।

– **अनिल तिवारी**

हरकतों को देखें तो इनकी साजिशों से सहज ही पर्दा उठने लगता है''। इन कंपनियों का भारत के आंतरिक व्यापार शेयर, बाजार में उतार–चढ़ाव और यहां तक कि आयात–निर्यात जैसे महत्व के मामले में भी इनका असर और दखल दिखता है। ये कंपनियां अपने फायदे के लिए हमारे देश के हुक्मरानों, नेताओं को ही नहीं बल्कि अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली ताकतों के बीच भी अपनी पैठ मजबूत करती हैं। सनद रहे कि उस दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसी ही ताकतों के बीच नजदीकियां बढ़ाने की हर संभव कोशिश करती थी। उनके द्वारा तत्कालीन राजाओं को खुश करने के किस्सों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं।

एक बात और जैसे आज के गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां धंधा तो भारत में करती हैं लेकिन इनके मुख्यालय सात समंदर पार उन देशों में स्थित हैं जहां से इनके आका चाबी भरते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एशिया में व्यापार फैलाने के लिए आई थी, पर उसके द्वारा की जाने वाली साजिशों का ताना–बाना बुनने का केंद्र बर्मिंघम पैलेस था। मालूम हो कि ऐसी कंपनियां केवल अपना हित देखती हैं। जरूरत पड़ने पर ये देशों को दंगों की आग में झोंकने से भी नहीं चुकती हैं। खासकर चुनाव के समय ऐसे नेताओं और दलों से गलबहिया करती हैं, जिससे उनकी कंपनियों द्वारा तय लक्ष्य पूरा होता रहे। यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये वही दल और नेता होते हैं जो गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में छपी खबर के आधार पर कभी देश को विदेश में बदनाम करते हैं तो कभी देश को नीचा दिखाने के लिए चीन और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक दुश्मन देशों के पक्ष में खड़े दिखते हैं।

ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही आज की ये विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीय संविधान की अनदेखी करते हुए अब केंद्र सरकार पर मौका देख आंखें भी तरेर रही हैं। अब समय बदल गया है। दुनिया के शक्तिशाली देशों का रुझान भूगोल से ज्यादा अर्थशास्त्र पर है। तब की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे देश के उर्वर भूगोल पर कब्जा करने के लिए निकली थी और अपने अभियान में बहुत हद तक सफल हुई थी। आज की यह तथाकथित कंपनियां देश के बाजार पर कब्जा करने की होड़ में लगी हैं। यही कारण है कि वह बाजार की आड़ में अपनी पसंद की राजनीति करने में लगी है, ताकि उनको फायदा पहुंचाने वाले और देश का नुकसान करने वाले नेता देश की सत्ता पर काबिज हो जाए।

आज की अमेरिकी कंपनियां व्यापार करते–करते हम भारतीयों को बताने लगी है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? लगता है देश का संविधान हम नहीं यह कंपनियां तय करेंगी? किसका पोस्ट हटाना है, किसका लगाना है या सोशल मीडिया के किस एकाउंट को रोकना है, किसको आगे बढ़ाना है, इसे तय करने का अधिकार भी ये कंपनियां अपने पास रखती हैं। इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, ये देश में आग लगाने वाली पोस्ट डालने वालों का नाम हमें आपको तो क्या, सरकार को भी नहीं बताएंगी? क्योंकि उनकी नजर में देश में आग लगाना भी अभिव्यक्ति की आजादी है। देशद्रोही ताकतों को पकड़वाने में मदद करने की बजाय ये उनके बारे में जानकारी छिपाने का काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी ताकतों के खिलाफ मुंह खोलने वालों का एकाउंट बंद कर देने की इनकी ओर से धमकी दी जाती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये कंपनियां ऐसी ताकतों से मिलकर लाबिंग भी करती है। मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद की फर्जी खबरें चलाई जाती है। ज्ञात हो कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के कड़े रुख के कारण पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा तो ये कंपनियां पाकिस्तान के पक्ष में प्रोपेगेंडा मशीन बन गई थी। पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़े गए। इमरान खान ग्रेट, इमरान फॉर पीस, गुडविल, जेस्चर जैसे कैंपेन चलाए गए। इन कंपनियों की नकल करते हुए भारत के कई नेताओं ने भी इमरान की तारीफ की तथा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने के लिए उन्हें संत तक कह डाला।

भले ही हम आप ऐसी कंपनियों को एक दूसरे से जुड़े रहने का साधन मानते हों, लेकिन यह देश तोड़ने का हथियार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है हमारे देश के विपक्षी राजनीतिक दल इनके पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? मामला चाहे पुलवामा का हो, गलवान का हो, या टूल किट का हो, ये कंपनियां सच बोलने की जगह सरकार को ही संविधान की याद दिलाने लगती है।

बाहरहाल इंटरनेट मीडिया को रास्ते पर आने की हिदायत देते हुए केंद्र की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय कंपनियां भारत के कानून का पालन करें। सरकार का मानना है कि ट्विटर ग्राहकों की आजादी पर मनमाना ब्रेक लगाती है और भारत के साथ पक्षपात भी करती है। ये कंपनियां अपने ग्राहकों का डाटा व्यापारिक हित साधने के लिए अन्य कंपनियों को भी देती हैं। सरकार के पास कई ऐसे सबूत है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भारत के हितों को लगातार नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। इन पर कड़े अंकुश की दरकार है। ❑❑

तलाशने होंगे परीक्षा के वैकल्पिक माध्यम

देश की भावी पीढ़ी के कर्णधार 2.60 करोड बच्चों को अब बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी होगी। महामारी के इस दौर में बच्चों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अब विद्यालयों में उपलब्ध विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन तथा अन्य जानकारियों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो परिस्थितियां सामान्य होने पर बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प बना रहेगा। यह वर्तमान परिस्थितियों में सबसे व्यवहारिक, सार्थक और स्वीकार्य कदम है। लेकिन इस निर्णय के बाद हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि एक वर्ष परीक्षा नहीं होने से देश की शिक्षा और छात्रों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी पूर्ति कैसे होगी? इस विषय पर मंथन करना आवश्यक है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्यों के शिक्षा बोर्डों के इस निर्णय के साथ एक नई चिंता सामने आ गई है कि बिना बोर्ड परीक्षा के अंक/ग्रेड कैसे दिए जाएंगे? विभिन्न संस्थानों में उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी? दरअसल लोगों की आशंकाएं निर्मूल नहीं है। किसी भी छात्र के जीवन में 12वीं की परीक्षा की बहुत अहमियत होती है। इसे छात्रों के जीवन का 'टर्निंग—प्वाइंट' कहा जा सकता है। इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर वे अपने आगे के जीवन में प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ रुख करते हैं।

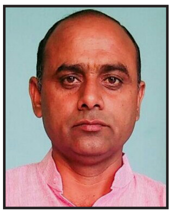

संकट की इस घड़ी में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी दष्टिगत रखते हुए माता—पिता अपने बच्चों को सार्थक और सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करें। कई छात्र परीक्षा होने या न होने की संभावना के कारण अनिर्णय की स्थिति में थे। जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव था।

– दुलीचंद कालीरमन

इसमें कोई संदेह नहीं कि कक्षा 12वीं में आंतरिक मूल्यांकन की एक वैध और सर्वमान्य व्यवस्था सुनिश्चित करना कठिन कार्य होगा। इसमें अंकस्फीति की संभावनाएं भी रहेंगी। जैसे की हाल ही में हरियाणा में दसवीं की परीक्षा परिणाम में देखने में आया है जिसमें अधिकतर छात्रों के अंक 90 प्रतिशत से अधिक आये हैं। ऐसे में अगर प्रतिभावान और कमजोर छात्र को एक ही मूल्यांकन पद्धति से प्रोन्नत किया जाएगा तो जिस भारतीय मेधा का लोहा दुनिया मानती है, उसकी साख पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। यह भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि कक्षा 12वीं के जिन विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम किया अब वह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए

परीक्षा का स्वैच्छिक विकल्प ही इसकी भरपाई कर सकता है।

बहुत समय से शिक्षाविद परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की बातें करते आ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद गठित तमाम शिक्षा आयोगों ने हमारी परीक्षा प्रणाली पर गहन चिंता व्यक्त की है और इसमें सुधार हेतु अनेक अनुशंसायें की हैं। कोरोना के इस संकट काल में अब समय आ गया है कि परीक्षा की दृष्टि से विद्यालयों को स्वायत्तता दी जाए और इस संबंध में नवाचार के लिए विद्यालयों को चिन्हित करें। ऐसे विद्यालयों की अपनी आतंरिक मूल्यांकन विधि हो जो बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित एवं मान्य हो।

बोर्ड की परीक्षा के साथ–साथ वर्ष भर रचनात्मक व सहभागिता पर आधारित सतत मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया जाए। जिसमें रिपोर्ट, समूह गतिविधि, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिसर्च आधारित गतिविधियां, ओपन बुक परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें छात्रों का समग्र मूल्यांकन हो सके। यदि इस वर्ष की भांति भविष्य में कभी परिस्थितियां पैदा होती है तो हमारे पास मूल्यांकन संबंधी आंकड़ों उपलब्धता रहे। जिससे परीक्षा परिणाम घोषित करने में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना हो।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाओं से छात्रों पर बोझ एवं तनाव निर्माण होता है इसलिए इसमें लचीलापन लाना होगा छात्रों का मूल्यांकन मात्र तीन घंटे की 'रटंत–पद्धति' पर आधारित सीमित अवधि के स्थान पर न होकर वर्षभर की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता, आचार–व्यवहार, प्रैक्टिकल कार्य, मौखिक परीक्षा इत्यादि के आधार पर होना चाहिए।

कोरोना काल में वर्षभर ई–लर्निंग तथा ऑनलाइन शिक्षा पर ही कार्य हुआ है। लेकिन इसके साथ–साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रश्न उठता है।

कोरोना काल में वर्षभर ई–लर्निंग तथा ऑनलाइन शिक्षा पर ही कार्य हुआ है। लेकिन इसके साथ–साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रश्न उठता है। कहीं पर डाटा कनेक्टिविटी की समस्या है तो कहीं पर मोबाइल–लैपटॉप की उपलब्धता नहीं है। लेकिन बदलते समय में राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित भी हो रही है। इस दिशा में केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर विकास के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि तकनीकी नवाचार का लाभ शिक्षा व परीक्षा में लिया जा सके।

परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर पर प्रवेश के नियमों का सूक्ष्म विवेचन करना होगा ताकि सारे प्रवेश पारदर्शी प्रक्रिया से हों। जो विद्यार्थी प्रवेश न पा सकें वे भी पारदर्शिता से संतुष्ट हो। यह कार्य कठिन है मगर विद्यार्थियों को और अभिभावकों को देश की संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। छात्रों को डर है कि आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर आया नतीजा उनकी आगे की राह में बाधित होगा। बहुत से अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने वाली है ऐसे में कुछ महीने बाद लिखित परीक्षा देकर अंक सुधार लेने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।

विश्व के अनेक डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार कहते रहे हैं कि यह महामारी तुरंत जाने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कोरोना के साथ–साथ जीने के लिए अभ्यस्त होना होगा। यह सही है कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब ये चिंता का विषय यह है कि क्या तीसरी लहर आएगी और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें इस प्रकार की स्थितियों में सुरक्षित और स्वस्थ रहकर आवश्यक व्यवस्थाएं निर्माण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसमें सरकार, अध्यापक वर्ग एवं अभिभावक आदि सभी की जिम्मेदारी है। संकट की इस घड़ी में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए माता–पिता अपने बच्चों को सार्थक और सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करें। कई छात्र परीक्षा होने या ना होने की संभावना के कारण अनिर्णय की स्थिति में थे। जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव था। यह अनिश्चितता की स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। परीक्षा रद्द करने का फैसला आना इन्हें सुकून ही दिलाएगा। ❑❑

बिन पानी सब सून

परंपरागत जल प्रबंधन की उपेक्षा का दुष्परिणाम

भारत में जल को सहेजने की, उसे पवित्र मानने की, उसे शुद्ध रखने की और उसे अगली पीढ़ियों को सुरक्षित देने की समृद्ध परंपरा एवं समृद्ध संस्कृति रही है। पिछले 7 दशकों में हमने जिस तरह आपनी इस संस्कृति को खोया है, उसने हमारी एक विशिष्ट पहचान को संकट में डाल दिया है। कोई समाज आधुनिकता की चकाचौंध अथवा बाहरी प्रभावों से इतना प्रभावित हो जाए कि वह अपनी विरासत खो बैठे तो उसे समाज का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा।

डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

बीते 7 जून को राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा में पानी के अभाव में 6 साल की एक मासूम बच्ची अंजलि ने तड़प तड़पकर दम तोड़ दिया। बच्ची के साथ उसकी नानी सुखी देवी थी, कण्ठ सुखने के कारण बेहोश होकर गिर गई। प्यास से हुई मौत की दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय जल मंत्री ने घटना को दुखद बताते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पानी के अभाव में हुई इस मौत को अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखदाई बताते हुए जल जीवन मिशन के मोर्चे पर राजस्थान सरकार की विफलता को इंगित किया है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की जांच कराने तथा राजनीतिक दलों से मौत पर राजनीति नहीं करने की बात कही है।

हमारी धरती के कुल जल भंडार का 97 प्रतिशत भाग समुद्र है। समुद्रों की औसत गहराई 1200 मीटर और महासागरों की करीब 4000 मीटर है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल साफ पानी का 24 प्रतिशत भाग भूमि के अंदर होता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। साफ पानी का 75 प्रतिशत भाग हिमनदी और बर्फ के रूप में जमा रहता है और बाकी मात्र 1 प्रतिशत नदियों, झीलों, जलाश्यों आदि में पाया जाता है। भारत में सतत बहने वाली 18 प्रमुख नदियां हैं। आमतौर पर प्राणियों और वनस्पतियों का 90 प्रतिशत भाग पानी होता है। मानव शरीर का दो तिहाई से अधिक का भाग पानी से बनता है। रक्त का 90 प्रतिशत भाग पानी है और मांसपेशियों का 85 प्रतिशत भाग पानी से बना होता है। एक मनुष्य साल भर में औसतन एक टन पानी पीता है। चारों ओर इतना पानी होने के बावजूद एक मासूम बच्ची चुल्लू भर पानी के लिए तड़प–तडपकर मर जाए, बच्ची की मौत से दुखी उसकी नानी सुखी पानी–पानी की रट लगाते हुए बेहोश होकर गिर जाए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, शासन सत्ता के संतुलनकारों को भी कटघरे में खड़ा करने वाला है।

बालिका अंजलि की मृत्यु पानी के अभाव में राजस्थान के रेतीले टीलों में हुई। किंतु पानी की किल्लत राजस्थान के साथ–साथ देश के अधिकांश हिस्सों में भी है। राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं तथा पानी के भयावह अकाल से त्रस्त ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। पशुओं को तिलक लगाकर छोड़ा जा रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सूखी नदियों के पात प्यास बुझाने के लिए फिर से खोदे जा रहे हैं कि शायद कहीं

पानी मिल जाए। पेड़–पौधे सूख रहे हैं और पशु प्यास से मर रहे हैं। सरकारी तंत्र इस विभीषिका से निपटने की कोशिश में है, परंतु सरकारी प्रयास असरकारी सिद्ध नहीं हो रहे।

प्रश्न उठता है कि आखिर पानी की इतनी कमी कैसे हुई? इसका सपाट उत्तर दिया जा सकता है कि कम बारिश और सरकारी लापरवाही के चलते यह दिक्कत आई लेकिन परंपरा कहती है कि नहीं हमने पानी को संभालने का, उसकी बूंद–बूंद को सहेजने का मूल्य ही नहीं समझा। पानी आसपास स्वाभाविक रूप से दिखता है और हम उसके प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। जिस राजस्थान में पानी का अकाल हुआ है, वहां पानी की बूंद–बूंद का मूल्य समझने वाला एक पूरा समाज था और उसका अपना एक अलग शास्त्र था। दूर से दूर गांव देहातों से लेकर चारागाहों तक और बियाबान से लेकर एकांत में बने मंदिर तक, पानी मिले इसकी चिंता हमारे समाज ने की थी। हमारे पुरखों ने पानी का मूल्य समझा था। फिर वह पानी चाहे बारिश का हो, नदी झरने का हो अथवा भूगर्भ का हो, पानी को संभालने की चिंता थी, उसके लिए योजना थी और एक योग्य तकनीक थी।

हमारे पुरखों ने जल का दोहन करते हुए हमेशा इस बात की भी योजना की कि धरती में जल बराबर बना रहे। धरती तो पानी की गुल्लक है और गुल्लक में बिना पैसा डाले लगातार पैसा कोई नहीं निकाल सकता। कल को अगर गुल्लक से पैसा चाहिए तो आज गुल्लक में पैसा डालना ही होगा। धरती से कल पानी चाहिए तो आज उसको पानी से समृद्ध बनाना ही होगा। परंतु पश्चिमी देशों की नकल के चक्कर में हम यह सीधा सा गणित आजादी के बाद से भुला बैठे हैं। हमने पहाड़ों को उनकी हरी चादर से वंचित किया तो उनसे बहने वाले पानी के सोते सूख गए। गांधीजी ने अपनी किताब 'हिंद स्वराज' में हिंसा और पर्यावरण विनाश तथा आधुनिक तकनीकी से उत्पन्न मानवीय भूल के खतरों को चिन्हित किया था। उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक चेतना तथा समाज की रचना को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। इसीलिए हमें जीवन की एक नई डिजाइन की दरकार है।

आज पानी की समस्या केवल राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की ही नहीं है, अपितु हर राज्य का हर शहर पानी की समस्या से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर–घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना भी लक्ष्य से पीछे है।

यूनेस्को और यूएन वाटर के सहयोग से तैयार वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व को अगले कई दशकों तक जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जल संकट से घिरे 122 देशों की सूची में भारत का 120वां स्थान है। दुनिया के सर्वाधिक जल समस्या ग्रस्त 20 शहरों में भारत के चार प्रमुख शहर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली शामिल हैं, जिनका नाम उक्त सूची में क्रमशः पहले, दूसरे, 11वें तथा 15वें स्थान पर अंकित है। द वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित 17 अन्य देशों में पानी की समस्या अत्यंत गंभीर है।

डब्ल्यूआरआई ने भूजल भंडार और उसमें आ रही निरंतर कमी, बाढ़ और सूखे के खतरे के आधार पर विश्व के 189 देशों को वहां पर उपलब्ध पानी को दृष्टि में रखकर श्रेणीबद्ध किया है। जल संकट के मामले में भारत विश्व में 131वें स्थान पर है। भारत के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बड़ी है, क्योंकि उसकी आबादी जल संकट का सामना कर रहे अन्य समस्याग्रस्त 16 देशों से 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के उत्तरी भाग में जल संकट भूजल स्तर के अत्यंत नीचे चले जाने के कारण अत्यधिक गंभीर है तथा 'डे जीरो' की कगार पर है। इस स्थिति में नलों का पानी भी सूख जाता है। विगत दिनों बंगलौर एवं चेन्नई में यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

देश के लगभग 70 प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए बाध्य हैं, जिसके चलते लगभग 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष प्रदूषित पानी पीने से बीमार होते हैं तथा लगभग 6 करोड लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए विवश हैं।

ऐसे में जलसुलभता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल को पूर्णरूपेण संरक्षित किया जाए तथा येनकेन प्रकारेण भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाया जाए। साथ ही इसके लिए पूर्णरूपेण सरकारों पर ही आश्रित न होकर जनभागीदारी एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त कर भारतीय परंपरा के अनुसार जल स्रोतों जैसे कुआ, बावड़ी, जोहड़ इत्यादि स्थान–स्थान पर खुदवाकर जहां एक ओर भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर समस्त जीव–जंतुओं को भी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। पूर्व में देश के सेठ साहूकारों एवं धन्ना सेठों द्वारा जल केंद्रों का निर्माण कराया जाता था, किंतु अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। भारतीय शास्त्रों उपनिषदों में जल केंद्रों के निर्माण को पुण्य कर्मों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है, किंतु आज नए निर्माण तो हो ही नहीं रहे, पुराने जल केंद्र एवं जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। उनके संरक्षण, संवर्धन की परम आवश्यकता है जिससे पानी की समस्या का निदान हो तथा भविष्य में न केवल अंजलि जैसी मासूम बच्ची को अकाल काल के गाल में समाना पड़े बल्कि समस्त जीव जंतुओं का जीवन भी बचाया जा सकेगा। ❑❑

हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत है?

"स्वास्थ्य का अधिकार" शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, इसे अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण विचार है कि पहले इसने भाग–4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या की और कहा कि यह राज्य का कर्त्तव्य है कि वह बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और इसलिए भारतीय संविधान के तहत प्रदान किया गया मौलिक अधिकार है। अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए अधिकारियों के रूप में सकारात्मक दायित्वों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य वितरण सुविधा की प्रणाली देश में इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इसका उद्देश्य पूरी आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आदिवासी आबादी, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, हिंसा के शिकार और हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रमुख संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण और पारंपरिक और स्वदेशी दवाओं की प्रणालियों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है। इनके अलावा, मंत्रालय तकनीकी सहायता के माध्यम से मौसमी बीमारी के प्रकोप और महामारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने में राज्यों की सहायता भी करता

भारत ने कई देशों को लाखों कोरोना वैक्सीन की खुराक और आपूर्ति करके इस मुश्किल समय में मानवता के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया है। इस कार्य के लिए विश्व स्तर पर भारत पर बरस रही वाहवाही के साथ–साथ हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा 'सर्वे संतु निरामया' का सार हमारे प्रयासों को शक्ति प्रदान कर रहा है।

सलिल सरोज

है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या तो सीधे केंद्रीय योजनाओं के तहत या स्वायत्त/सांविधिक निकायों आदि और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में खर्च करता है। 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अलावा, मंत्रालय नामित क्षेत्रों में एड्स, मलेरिया, कुष्ठ, क्षय रोग और दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग केवल राज्यों को बाहरी सहायता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना है जहां बीमारी की घटनाएं अधिक हैं।

कोविड–19 महामारी के मद्देनज़र भारत दुनिया में कोविड–19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। कोवैक्सीन और कोविडशिल्ड दो टीके हैं जिन्हें कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोल आउट किया गया है, जिनका निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा क्रमशः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। भारत ने कई देशों को लाखों कोरोना वैक्सीन की खुराक और आपूर्ति करके इस मुश्किल समय में मानवता के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया है। इस कार्य के लिए विश्व स्तर पर भारत पर बरस रही वाहवाही के साथ–साथ हमारी सदियों

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुरानी सांस्कृतिक परंपरा 'सर्वे संतु निरामया' का सार हमारे प्रयासों को शक्ति प्रदान कर रहा है। कोविड–19 महामारी को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार एलोपैथी को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

भारत के 104 मिलियन आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार स्वास्थ्य और पोषण लक्ष्यों को पूरा करने की देश की क्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की कुल आबादी की तुलना में आदिवासी समुदाय उच्च मातृ और पांच वर्ष से कम उम्र के लोगों की मृत्यु दर से पीड़ित हैं; बौने, कमजोर और कम वजन वाले बच्चे; मलेरिया और तपेदिक की उच्च घटना; और मधुमेह, हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप का एक उच्च और बढ़ता बोझ। आकांक्षी जिले कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी आबादी के समग्र कल्याण को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं जिसमें इन जिलों के समग्र मूल्यांकन में "स्वास्थ्य और पोषण" को प्रमुख संकेतकों में से एक के रूप में बनाए रखा जाता है। इन जिलों में प्रशासन के सभी स्तरों पर सहयोग, स्वास्थ्य संकेतकों की रीयल टाइम ई–मॉनिटरिंग और जनभागीदारी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं। स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इन जिलों में ममता ब्रिगेड, जन्म साथी कार्यक्रम, जन्म प्रतीक्षा गृह, सास बहू सम्मेलन, किलकारीः टैबलेट आधारित आईईसी, लाइफलाइन एक्सप्रेस और सिरहा गुण सम्मेलन जैसी अनूठी पहल की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021–22 के मूल में स्वास्थ्य और भलाई को रखकर सरकार ने बजट आवंटन के पैटर्न में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। इस बजट ने स्वास्थ्य और भलाई को विकास और विकास के छह मूलभूत स्तंभों में सबसे शीर्ष के रूप में स्वीकार किया है और स्वास्थ्य के समग्र क्षेत्र के साथ–साथ स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5–3 प्रतिशत करने की जोरदार सिफारिश की है। यह नोट करता है कि यह आउट–ऑफ–पॉकेट–व्यय (ओओपीई) को काफी कम कर सकता है जो कुल स्वास्थ्य देखभाल खर्च का 35 प्रतिशत है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ❑❑

(ईमेल द्वारा)

स्वदेशी जागरण मंच

राष्ट्रीय परिषद बैठक (तरंग)

(जून 5–6, 2021)

स्वदेशी जागरण मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिनांक 5–6 जून 2021 को तरंग माध्यम से संपन्न हुई। चार सत्रों में आयोजित इस राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ 5 जून शनिवार सायं 5:30 बजे हुआ। इस बैठक में अ.भा. संयोजक श्री आर. सुंदरम व केंद्रीय अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्र–प्रांत के संयोजक, संगठक व नवनियुक्त राष्ट्रीय परिषद सदस्यों सहित 264 कार्यकर्ताओं ने सहभाग किया। विविध क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित हुए।

प्रथम सत्रः 5 जून सायं 5:30 से 7:00

प्रथम सत्र में मंच का संचालन करते हुए अ.भा. सहसंयोजक श्री अजय पत्की ने इस बैठक की प्रस्तावना भी रखी व स्वदेशी जागरण मंच की गत गतिविधियों की चर्चा भी की। कोरोना के कारण से जो अपने कार्यकर्ता या देश के बंधु–भगिनी दिवंगत हुए, ऐसे सब लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आधे मिनट का मौन भी रखा गया।

इस सत्र में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना का वृत्त आया। क्षेत्र संयोजक श्री मंजूनाथ ने बताया कि वहां इस दौरान संपूर्ण क्षेत्रों में कार्यकर्ता न केवल रोगियों की सेवा में रत रहे, बल्कि चल रहे हस्ताक्षर अभियान में भी दिन रात लगे हुए हैं। इसी प्रकार पश्चिम, मध्य, राजस्थान व उत्तर क्षेत्र के प्रांतों का भी गत मार्च से हुई गतिविधियों का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जो अत्यंत प्रेरक था। सबने यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसन अभियान की विशेष रूप से चर्चा की।

इसके पश्चात मंच के अ.भा. प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने भूमि सुपोषण अभियान के अंतर्गत, संपूर्ण देश में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कैसा परिश्रम किया और उसको समाज का कैसा उत्तम प्रतिसाद मिला, इस विषय में बताया। कर्नाटक के संगठक श्री के. जगदीश ने आयुर्वेद व स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों से बेंगलुरु के डॉ. गिरिधर काजे द्वारा कोरोना के उपचार की जानकारी देते हुए बताया कि 7 लाख से अधिक लोगों ने यह आयुर्वेदिक दवा ली है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव ने भी इस विषय में सहयोग किया। इसी सत्र में डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी ने भीलवाड़ा जिले के डिजिटल हस्ताक्षर अभियान के सफल प्रयोगों को भी सबके साथ साझा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व स्वदेशी शोध संस्थान के प्रभारी डा. विजय कौल ने भारत को विश्व में चिकित्सकीय आधारभूत संरचना में विश्व का नेतृत्व करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत कैसे कम लागत में उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों के निर्यात का वैश्विक केंद्र बन सकता है, इस विषय की चर्चा भी की। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के

प्रस्ताव–1

भारतः वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और अग्रिम संभावनाएँ

कोविड–19 अथवा कोरोना वायरस ने पिछले 18 महीनों से सम्पूर्ण मानवता को बुरी तरह प्रताड़ित करके रखा हुआ है। वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से सम्पूर्ण विश्व में वैक्सीन (टीका) खोज की तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और बड़ी सफलताएँ भी प्राप्त हुई। सभी देश अपने नागरिकों को टीका लगाने के लिए एक विशाल टीकाकरण अभियान में तो जुट ही गये है साथ ही महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन भी लगा रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि महामारी के कारण होने वाले इस भयंकर अभूतपूर्व तबाही को समाज के हर वर्ग के एकीकृत ठोस प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है।

कठोर लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों से न केवल विश्व अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़े हैं जिनके कारण परिवहन (उड्डयन, रेल, सड़क व जल यातायात), पर्यटन, शिक्षा, खुदरा व्यापार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि क्षेत्रों में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारी छंटनी करनी पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) के अनुसार 2019 के अंतिम तिमाही की तुलना में 2020 के अंतिम तिमाही में 8.8 प्रतिशत वैश्विक काम करने के घंटों में कमी आई जो कि 25.5 करोड़ नौकरियों समाप्त होने के समान है। ये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से उभरी आर्थिक मंदी में नष्ट हुई नौकरियों का भी चार गुना है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी स्टैंडर्ड एंड पूर्स (Standard & Poor's (S&P)) के अनुमान के अनुसार भारत में चल रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अप्रैल–जून तिमाही में 210 मिलियन डालर (1536 करोड़ रुपये) के प्रतिदिन उत्पादन का नुकसान हो रहा है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 4.3 प्रतिशत की संकुचन दर रही और यू.एस.ए. (संयुक्त राज्य अमेरिका) के सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत, यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) में 7.4 प्रतिशत, जापान में 5.5 प्रतिशत और उभरते व विकासशील देशों में 2.6 प्रतिशत की संकुचन दर रही। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत भी इस वैश्विक महामारी से पिछले वर्ष प्रभावित हुआ जिसके फलस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत की संकुचन देखी गयी। फिर भी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021–22 में भारत 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। भारत ने महामारी की पहली लहर का बड़े ही प्रभावशाली तरीके से सामना किया और आर्थिक मंदी से उभरना शुरू किया परंतु अप्रैल 2021 में आयी दूसरी लहर ने एक और झटका देते हुए अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचाई हैं।

भारत सरकार ने इस बार राष्ट्रव्यापी सम्पूर्ण लॉकडाउन न लगाकर राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी ताकि वे अपने राज्य की कोरोना स्थिति अनुसार लॉकडाउन का प्रारूप तय कर सके। इससे कृषि, लघु, मध्यम व भारी उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन चलता रहा। फिर भी 2020 में अप्रैल से मई तक लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से 10 करोड़ नौकरियों समाप्त हो गयी और वर्तमान में मई 2021 में लॉकडाउन के चलते 1.53 करोड़ नौकरियाँ नष्ट हो गयी और देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 18 प्रतिशत हो गयी।

एक हालिया रिपोर्ट (स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021ः कोविड–19 का एक वर्ष, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय) इस बात पर प्रकाश डालती है कि यदि चार सदस्यों का एक औसत घर माना जाए, तो जो जनवरी 2020 में रुपये 15,989 मासिक प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी वह अक्टूबर 2020 में घटकर रुपये 14,979 पर आ गई है। युवा श्रमिकों (15–24 वर्ष आयु वर्ग) के बीच बेरोजगारी अधिक है जो रोजगार की पुनः प्राप्ति में विफल रहें हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में महामारी के दौरान अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है क्योंकि वेतन भोगी कर्मचारी स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी गतिविधियों की ओर बढ़ गए हैं।

यह एक पूर्व विदित निष्कर्ष है कि स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में कमी ने गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है, गरीबी के स्तर में वृद्धि की है और धन असमानताओं में योगदान दिया है।

दूसरी ओर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा पाया गया कि अप्रैल–जून 2020 के दौरान भारत की घरेलू बचत जीडीपी के 28.1 प्रतिशत से घटकर 22.1 प्रतिशत हो गई जो एक गंभीर संकेत है। घटती घरेलू बचत और गिरती आय का परिवार की घरेलू खपत और स्वास्थ्य देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है। निशुल्क राशन, नकद हस्तांतरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान भुगतान, पेंशन भुगतान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) और आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे सरकारी राहत उपायों ने 2020 में महामारी से प्रभावित जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग को सुखदायक प्रभाव प्रदान किया है। स्वदेशी जागरण मंच कोरोना वायरस के कारण उपजे वर्तमान स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार की राजकोषीय प्रोत्साहन नीति और 4 जून 2021 को सेवा क्षेत्र को 15,000 करोड़ ऋण की घोषणा की सराहना करता है। स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि महामारी के कारण होने वाले इस भयंकर तबाही को समाज के हर वर्ग के एकीकृत ठोस प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। देश की इस अभूतपूर्व कठिन परिस्थिति में, स्वदेशी जागरण मंच अपील करता है–

1. निशुल्क खाद्य अनाज के अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों को राजकोषीय सहायता देने पर विचार कर अमल करना।
2. ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत निधि आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की जाए।
3. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कुछ और महीनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी परिधि में महामारी से ग्रसित अन्य आर्थिक क्षेत्रों को भी लाया जा सकता है।
4. कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों जैसे परिवहन, पर्यटन, विमानन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन के रूप में नरम ऋण घोषित करना।
5. मध्यम छोटे और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) पैकेज की घोषणा करना।
6. भारतीय रिजर्व बैंक को स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के आवश्यकता अनुरूप ऋण अधिस्थगन (लोन मोरटोरियम) घोषणा करनी चाहिए और उदार मौद्रिक समर्थन के लिए बैंकों को निर्देशित करना चाहिए।
7. कोविड राहत के लिए कॉर्पोरेट और व्यापारिक संस्थानों को उदार योगदान देकर कठिन स्थिति का प्रबंधन करना चाहिए, बिना किसी छंटनी के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान और मध्यम छोटे और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों के बिलों का समय पर भुगतान।

8. निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इस विकट परिस्थिति में लाभ हानि के विचार त्यागकर न्यूनतम लागत के साथ उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

इस महामारी ने इस भ्रम को दूर कर दिया है कि शहरीकरण ही विकास का एकमात्र उपाय है। यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से, दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है, जिससे पर्याप्त रोजगार देने वाला विकेंद्रीकृत विकास मॉडल का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में, स्वदेशी जागरण मंच आह्वान करता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इन अद्वितीय कठिन परिस्थितियों में पारस्परिक सहयोग से हर संभव तरीके से एक–दूसरे की सहायता करनी चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच दृढ़ता से भारत की अंतर्निहित ताकत में विश्वास करता है जो वर्तमान कठिन परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। आईए हम सभी आपसी विश्वास के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत को इसका वैभव और गौरव पुनः प्राप्त हो सके। ❑

कुलपति और स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय अधिकारी प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने पेटेंट फ्री वैक्सीन की प्रक्रिया और औषधियों की आवश्यकता और उत्पादन को सर्वसुलभता बनाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस हेतु उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि हमें नवाचार, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और विश्व की आवश्यकताओं को देखते हुए योजना करनी होगी। उन्होंने कहा कि "पेटेंट करने वाली कंपनियों के मुनाफे से कहीं अधिक आवश्यक है लोगों की जीवन रक्षा, जो उनका मौलिक अधिकार है।"

द्वितीय सत्रः 5 जून सायं 7:00 बजे

द्वितीय सत्र का संचालन अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ धनपतराम अग्रवाल द्वारा किया गया। चार क्षेत्रों– पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पूर्वी क्षेत्र का वृत्त प्रस्तुत हुआ और वहां गत दिनों हुए स्वदेशी मेला, वेबीनार, भूमि सुपोषण, महिलाओं के कार्यक्रम की अच्छी जानकारी दी गई। अ.भा. संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने पूर्वोत्तर में स्वदेशी कार्य प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। इसी सत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र संगठक श्री अजय उपाध्याय ने पंडित दीनदयाल अनुसंधान एवं आरोग्य केंद्र द्वारा प्रशिक्षण, दोना पत्तल उत्पादन की निशुल्क मशीन आदि देने व स्वरोजगार पर चल रहे प्रयोगों के बारे में बताया।

मंच के अ.भा. सहसंयोजक डॉ अश्वनी महाजन ने कोरोना के प्रारंभ को लेकर विश्व में इस समय चल रही चिंताओं और चर्चाओं के बारे में बताया और कहा कि चीन की संदेहास्पद भूमिका का विवेचन अब भारत से लेकर अमेरिका तक में हो रहा है। उन्होंने बताया कि चीन के वुहान स्थित लैब में इसके उद्भव और वहां से लीक होने के पुष्ट प्रमाण विश्व भर में मिल रहे हैं।

तीसरा सत्र 6 जून प्रातः 9:30

इस सत्र का संचालन दक्षिण मध्य क्षेत्र के श्री मंजूनाथ ने किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति व उत्तर क्षेत्र सह संयोजक प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने वैश्विक वेबीनार व भारत में उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा अब तक 2120 प्रबुद्धजनों के हस्ताक्षर के विषय में बताया। जॉइन स्वदेशी डॉट कॉम के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और हरियाणा उच्च शिक्षा कौन्सिल के सम्मिलित प्रयासों से हुए वैश्विक वेबीनार की सब तरफ चर्चा हुई ही है। जिसमें अमेरिका के सीनेटर व हारवर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डीन नरेंद्र रूस्तगी उपस्थित थे। इसी प्रकार भारत में हुए एक बड़े वेबीनार की जानकारी भी वहां मिली, जिसमें स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज, नितिन गडकरी जी व केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया जी का मार्गदर्शन भी मिला। भारत में अभी तक 7.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी सत्र में सी.ए. बलराम नंदवानी ने स्वदेशी शोध संस्थान व निधि संचय की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इस भवन का भूमि पूजन संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी के द्वारा संपन्न हुआ और यह जल्दी ही आकार लेगा।

मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम ने कोविड–19 के बाद की आर्थिक पुनर्रचना विषय पर प्रस्ताव रखा। रोजगार उत्पादन के नए अवसर के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इस विषय पर हमारा दृष्टिकोण क्या है, यह भी प्रस्ताव में रखा। इसी प्रकार दक्षिण विचार विभाग प्रमुख डॉ. लिंगामूर्ति ने कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था और रोजगार के प्रस्ताव पर बात करते हुए कहा की धार्मिक पर्यटन, स्वरोजगार के लघु माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत रोजगार की वृद्धि होती है। इसी सत्र में ही अ.भा. सह संयोजक श्री अरुण ओझा ने डंकल प्रस्ताव, उरूग्वे राउंड तथा विश्व के प्रमुख तीनों आर्थिक संगठनों की भूमिका की विवेचना की। डॉ. अश्वनी महाजन ने नाटको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजीव नन्नापानीनी का परिचय कराया। जिन्होंने सबसे पहले भारत में कंपलसरी लाइसेंस प्राप्त कर लीवर के कैंसर की दवाई को मात्र 10 प्रतिशत मूल्य पर भारत और विश्व को उपलब्ध करवाया था। वह इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उन्होंने मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों द्वारा 20 साल की पेटेंट अवधि के बाद भी इसको 30–40 साल तक बढ़ाए जाने के विचार की आलोचना की। और कहा कि विश्व को सस्ती, सुलभ चिकित्सा व्यवस्था देनी है तो इस पेटेंट के समय को कम ही करना होगा।

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जारी वक्तव्य

वायरस की उत्पत्ति की द्रुत गति से जाँच की जरूरत

पिछले 15 महीनों में दुनिया और इंसानियत पर कहर ढाने वाले इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानने का हर किसी को अधिकार है। यह मुद्दा, कि कोरोना वायरस, जो महामारी का कारण बना, वुहान (चीन) में एक प्रयोगशाला में बनाया गया था, जो जानबूझ कर या गलती से प्रयोगशाला से बाहर आया था, लगभग शुरू से ही चर्चा में रहा है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे बार–बार 'चीनी वायरस' बता रहे थे।

हाल ही के कई नए शोध निष्कर्षों से पता चला है कि वायरस वास्तव में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ था। यह समझना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की उत्पत्ति का अध्ययन तो कर रहा है, लेकिन केवल प्रतीकात्मक रूप से। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्रोत को जाने बिना हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वायरस को प्रयोगशाला से छोड़ा गया था और मार्च 2021 में प्रकाशित इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि यह चीन के पशु बाजार से निकलने वाला वायरस था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वायरस चमगादड़ से निकला था और दूसरे जानवर के जरिए इंसानों में दाखिल हुआ था। हालांकि, रिपोर्ट ने वुहान की प्रयोगशाला से इसकी उत्पत्ति से भी इंकार नहीं किया।

चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के भारी दबाव में है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से वायरस की उत्पत्ति को वुहान प्रयोगशाला से नहीं जोड़ पाया है। लेकिन इस आशंका से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, संगठन ने इस रिपोर्ट को 'अनिर्णीत' बताकर अमेरिका को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। साथ ही रिपोर्ट में शामिल हर संबंधित मुद्दे पर कहा गया है कि इसके लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है। लेकिन विशेषज्ञों के एक बड़े समूह ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और वे लगातार इस पर आगे की जांच कर रहे हैं। हाल के महीनों में, कई अध्ययन और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से वुहान प्रयोगशाला से वायरस के जानबूझकर या आकस्मिक रिसाव का संकेत देते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर विशेषज्ञों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन मुद्दों की जांच नहीं की जो उसे करना चाहिए था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के बीच नापाक् रिश्ते

विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके प्रमुख श्री टेड्रोस अधानोम इस महामारी की शुरुआत से ही संदेह के घेरे में हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक श्री केन रोथ ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 'संस्थागत मिलीभगत' का दोषी है। उन्होंने यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस बयान के संदर्भ में कही, जो चीन के झूठ की अंध–स्वीकृति से निकला था, जब उसने जनवरी 2020 में इस वायरस के मानव से मानव में संचरण से इनकार किया था। इसलिए, डब्ल्यूएचओ वास्तव में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का 86 मिलियन फंड चीन से आता है, 532 मिलियन गेट्स फाउंडेशन से और 371 मिलियन गेट्स फाउंडेशन की अपनी रचना, 'गावि अलाइयन्स' से आता है। यही कारण है कि यह संगठन चीन और गेट्स फाउंडेशन के जबरदस्त प्रभाव में है। गौरतलब है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आ रही इन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए कि वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कभी भी चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। बिल गेट्स ने भी चीन का बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वास्तव में चीन ने महामारी के प्रकोप के बाद से बहुत अच्छा काम किया है और यह कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक 'अभूतपूर्व' संगठन है। यानी यदि सूत्रों को जोड़ें तो हम चीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और गेट्स फाउंडेशन के बीच के अपवित्र संबंध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यह भी कोई रहस्य नहीं है कि श्री टेड्रोस अधानोम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने में चीन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह घिनौना रिश्ता किस तरह दुनिया में तबाही मचा रहा है यह भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। यह वायरस, इसे कोरोना वायरस कहें, वुहान वायरस या चीनी वायरस, चीन और चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से (गलती से या जानबूझकर) निकाला और इसके बारे में नवंबर 2019 में पता चला, लेकिन इस संबंध में दुनिया को जनवरी के अंत तक जानकारी दी गई। इस देरी में साजिश भी परिलक्षित हो रही है। गौरतलब है कि 14 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर इस वायरस के मानव–से–मानव संक्रमण से इंकार किया था। डब्ल्यूएचओ के ट्वीट में कहा गया है, "चीनी अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में #कोरोनावायरस (#वुहान #चीन में पहचाने गए 2019–nCoV0) के मानव–से–मानव संक्रमण का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस रवैये के कारण इतने भयानक वायरस के बावजूद मानव–से–मानव संक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सका। चीन से दुनिया भर के देशों के लिए उड़ानें बेरोकटोक जारी रहीं और यह वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैल गया। इस भूल की जिम्मेदारी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं ली। हालांकि, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की और इसकी फंडिंग भी रोक दी गई। हालांकि किसी अन्य देश ने इतना कठोर कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की छवि को बड़ा झटका लगा है।

नवीनतम जानकारी

वाशिंगटन पोस्ट में लेखों और कई अन्य शोध अध्ययनों ने अब इस खेल में चीन के साथ अमेरिका के संस्थानों और व्यक्तियों की भागीदारी का भी खुलासा किया है।

सामने आ रहे तथ्यों के अनुसार, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता 'गेन ऑफ फंक्शन' रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका उद्देश्य उच्च संक्रामकता वाले कोरोनावायरस के काइमेरिक संस्करण विकसित करना था, यानी वह प्रयोग जिसने संभवतः वायरस कोविड–19 को विकसित किया गया। इस तथ्य को कई वैज्ञानिक प्रकाशनों और प्रसिद्ध विज्ञान लेखकों जैसे निकोलस वेड द्वारा प्रकाश में लाया गया है। यह स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रकाशित डेटा हैं कि कोविड–19 की आनुवंशिक संरचना में प्रयोगशाला में इंजीनियरिकृत एक काइमेरिक वायरस के हस्ताक्षर हैं।

इस संदर्भ में मिस्टर पीटर दासज़क की भूमिका और भी संदिग्ध है। यह सज्जन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वुहान भेजे गए आयोग के अहम सदस्य रह चुके हैं। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 'लैंसेट' नाम की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि वायरस के प्रसार में प्रयोगशाला की कोई भूमिका नहीं है।

लेकिन पत्र में यह नहीं बताया गया कि पीटर दासज़क न्यूयॉर्क स्थित 'इको हेल्थ एलायंस' के माध्यम से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी हितों के टकराव का खुलासा नहीं किया गया था। चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का दबदबा है, इसलिए वायरस के उद्भव की जांच करने हेतु इसके द्वारा भेजे गए आयोग द्वारा की गई जांच भी संदेह के घेरे में आती है।

इन लोगों के अलावा, कुछ बहुत ही उच्च पदस्थ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 'गेन ऑफ फंक्शन्स' शोध के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी और आगे जांच की आवश्यकता होगी ताकि मानव जाति के लिए कहर पैदा करने वाले इतिहास की सबसे खराब महामारी के वायरस की उत्पत्ति के बारे में निर्णायक सबूत तक पहुंच कर उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके।

स्वदेशी जागरण मंच भारत और दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय और वैश्विक नेताओं से वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए ठोस प्रयास करने और वायरस के निर्माण और प्रसार में शामिल लोगों या देशों की जिम्मेदारी तय करने का आह्वान करता है। यह नुकसान के मुआवजे के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी स्थिति फिर कभी उत्पन्न न हो। ❑

इसके पश्चात श्री अजय पत्की ने प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा व श्री सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक "वैश्विक महामारी कोरोना, चुनौती व समाधान" के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह अन्य भाषाओं में भी अनुवादित होकर शीघ्र सबको उपलब्ध होगी। सत्र के समापन में श्री सतीश कुमार ने पेटेंट फ्री वेक्सीन अभियान के उद्देश्य व वैश्विक दृश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में 20 लाख से अधिक लोगों ने और 200 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ने इसकी मांग की है। डब्ल्यूएचओ के मुखिया से लेकर दुनिया के 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब इस मांग के समर्थन में आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन व जापान चीन तक का भी समर्थन मिल रहा है। यह सत्य पर आधारित अभियान है जिसे सफल होना ही है।

चौथा सत्र 6 जून प्रातः काल 11:30 बजे

इस समापन सत्र का संचालन अ.भा. विचार विभाग प्रमुख प्रो. राजकुमार मित्तल (वीसी) ने किया। इस सत्र में पद्मश्री डॉ रजनी कांत द्विवेदी ने भौगोलिक संकेतक (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) टैग की जानकारी दी। उन्होंने स्वयं भी 53 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाया है। और काशी में ही 9 जनपदों के 20 लाख बुनकरों के (इसकी सहायता से) कारोबार में 32 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में केवल 370 जीआई टैग पंजीकृत हुए हैं। जबकि चीन में 9000 व अमेरिका में 4000 हैं। हमें इस दृष्टि से बहुत प्रयत्न करने चाहिए।

इसके पश्चात अखिल भारतीय महिला प्रमुख बहन अमिता पत्की ने तिलक जी के प्रसंग के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान में नारी शक्ति की भूमिका को सबके सामने रखा। मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने आगामी योजनाओं का खाका सबके सामने प्रस्तुत किया। जिसके अंतर्गत –

1. 12 जून सायं से 13 जून सायंकाल तक एक दिवसीय विशेष हस्ताक्षर अभियान सब कार्यकर्ता, परिवार सहित चलाएं।
2. 14 जून को UAVM विषय की एक अंतरराष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।
3. 20 जून को भारत के सभी 739 जिलों व विश्व के सभी देशों में विश्व जागृति दिवस मनाया जाएगा और पेटेंट फ्री वैक्सीन की मांग को सर्वदूर समर्थन दिलवाया जाएगा।
4. लाकडाउन के बाद स्वदेशी शोध संस्थान के लिए धन संग्रह पुनः शुरू करना है।
5. जुलाई व अगस्त माह में प्रांत अनुसार विचार वर्ग करने हैं।

राष्ट्रीय परिषद बैठक का समारोप करते हुए संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री भगैय्या जी ने सभी कार्यकर्ताओं को हस्ताक्षर अभियान में पूरी शक्ति से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने न केवल सेवा कार्य किये, बल्कि विविध संगठनों, बुद्धिजीवियों, अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग लेते हुए यह अभियान भी चलाया है। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण व चिकित्सा प्रणाली का भी समर्थन किया। कार्यकर्ता निर्माण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, हृदय में आग रखकर काम करना चाहिए। यह काम हम संपूर्ण मानवता के लिए कर रहे हैं, सब संगठनों का इसमें सहयोग मिलेगा।

अंत में राष्ट्रीय संयोजक श्री सुंदरम जी ने नवीन घोषणाएं करते हुए नई बनी राष्ट्रीय परिषद की जानकारी भी दी और उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि न केवल हम कोरोना की बीमारी से बहुत अच्छे ढंग से निकलेंगे, बल्कि हम अपनी अर्थव्यवस्था व रोजगार को भी अच्छी तरह संभाल लेंगे। उन्होंने अगले 6 वर्षों में लेस चाइना से चाइना लेस ईकोनोमी का विचार भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर राजकुमार मित्तल ने सबका धन्यवाद किया और वंदेमातरम के सस्वर पाठ के साथ परिषद की यह बैठक संपन्न हुई। ❑❑

(अन्य दो प्रस्ताव अगले अंक में प्रकाशित किये जायेंगे।)

स्वदेशी जागरण मंच आयोजित करेगा 20 जून को 'विश्व जागृति दिवस'

पूरे विश्व में 20 जून 2021 को सुबह 11 बजे स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कोविड वैक्सीन को पेटेंट मुक्त बनाने के लिए "विश्व जागृति दिवस" का आयोजन किए जाने वाला है। संपूर्ण विश्व में सभी को दो–दो डोज कोविड वैक्सीन की मिले, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच पूरे विश्व में डिजिटल पिटिशन हस्ताक्षर करवा रहा है, जिस पर भारत में अब तक कुल 20 लाख (18 जून तक) लोगों ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। पेटेंट मुक्त वैक्सीन कीमांग में तेजी लाने के लिए ही विश्व जागृति दिवस का आयोजन हो रहा है।

इस बारे में बताते हुए स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच सदैव ही भारतीयता और मानव मन को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता रहा है। प्रारंभ से ही वैश्वीकरण की चुनौतियों से समाज को जागरूक करता रहा है। साथ ही विकसित देशों के दृष्टिकोण, डब्ल्यूटीओ, जी–7 के देशों और फार्मा कंपनियों के नीति और नियत पर प्रश्न पूछा है। उत्तर भी दिया है।

उन्होंने कहा कि आज कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है और आज की परिस्थिति में यह अनिवार्य कर दिया है कि संपूर्ण विश्व को कोरोना वैक्सीन की दो–दो डोज अतिशीघ्र लग जाए, नहीं तो संपूर्ण मानवता किसी भयंकर चुनौती में फंस सकती है। ऐसे समय में स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट मुक्त कोरोना वैक्सीन की मांग संपूर्ण दुनिया में उठाई है। जिसे विकासशील देशों का समर्थन मिलता जा रहा है।

https://newstrack.com/country/swadeshi-jagaran-manch-patent-free-vaccine-international-awareness-day-20-june-272253

दुनिया पूछ रही है 'कहां से आया कोरोना वायरस'

पिछले 15 महीनों से दुनियाभर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर उठे विवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब कूद गया है। हाल ही में किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि यह वायरस चीन के ही वुहान इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी में उत्पन्न हुआ था। इसी तरह नए लेखों में इस मामले में चीन व अमेरिका के संस्थानों और व्यक्तियों की भागीदारी की बात भी सामने आ रही है।

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि हर किसी को यह जानने का अधिकार है कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है और यह वायरस लैब से बाहर कैसे आया। इसमें कुछ उच्च पदस्थ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इसमें

वुहान इंस्टीट्यूट की मदद की। मंच ने इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) व बिल गेट्स फाउंडेशन की भूमिका संदिग्ध बताते हुए देश–दुनिया के विज्ञानियों व वैश्विक नेताओं का आह्वान किया है कि विज्ञानियों को इसकी जड़ तक पहुंचकर इसके प्रसार में शामिल लोगों व देश की जिम्मेदारी को तय करना चाहिए, ताकि इससे हुए नुकसान के मुआवजे की भरपाई का रास्ता साफ होने के साथ सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी भयावह स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो सके।

मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि शुरू से ही यह वैश्विक बहस के केंद्र में है कि चीन के वुहान स्थित लैब से बाहर आया है। इसलिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे बार–बार 'चीनी वायरस' बताते रहे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों में उत्पत्ति का पता लगाने को कहा है।

महाजन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को चीन, गेट्स फाउंडेशन व इसके अन्य संगठनों से बड़ा पैसा आता है। यही कारण है कि यह संगठन चीन और गेट्स फाउंडेशन के दबाव में है। हालांकि, चीन को क्लीनचिट देने की उसकी जांच रिपोर्ट को दुनिया भर के ज्यादातर विशेषज्ञों ने सिरे से खारिज कर दिया है। सभी का कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने उन मुद्दों की जांच नहीं की, जो उसे करना चाहिए था।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-this-voice-is-coming-from-every-corner-of-the-world-find-out-where-coronavirus-originated-from-jagran-special-21724769.html

मुफ्त टीकाकरण के लिए स्वदेशी जागरण मंच का जागरुकता अभियान

स्वदेशी जागरण मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत संयोजक अनिल लुहारी ने बताया कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। मानवता की रक्षा का एक मात्र उपाय है समस्त संसार का टीकाकरण हो, इसके लिये कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करना अनिवार्य है, पेटेंट मुक्त वैक्सीन अभियान मे संसार के 120 से अधिक देश जुड़ गये है। यदि विश्व में कही भी कोविड 19 वाइरस रह गया तो वो मानवता के लिए

खतरा है ऐसे मे आवश्यक है कि गरीब देश भी टीकाकरण करवाये इसके लिये जरूरी है कि मँहगी कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री किया जाये। इस हेत स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व कल्याण के लिये सर्व–सुलभ टीकाकरण अभियान चला रखा है। जिसमे डिजिटल पीटिशन हस्ताक्षर अभियान मे अब तक 20 लाख से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुये हैं।

इस दौरान उन्होंने बताया कि पेटेंट मुक्त कोरोना वैक्सीन के बारे में अधिक जनजागरण हेतु स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रत्येक जिले मे 20 जून को 2021 विश्व जागृति दिवस का आयोजन कर रहा है, जिससे कोरोना नियमों एवम सोशल डिस्टेन्शिग का पालन करते हुए जिले भर के मुख्य स्थानों पर जागृति कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस दौरान प्रांत प्रचार प्रमुख मानवेंद्र सिंह जिला संयोजक संदीप गुप्ता, नगर संयोजक सार्थक जी, मीडिया प्रभारी अजयकान्त, विचार मंडल प्रमुख संजय आहूजा, नगर सहसंयोजक प्रवीण, अक्षय आदि उपस्थित रहे।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/muzaffar-nagar/story-patent-free-corona-vaccine-world-awareness-day-swadeshi-jagran-manch-4132829.html

पेटेंट मुक्त हो कोरोना का टीकाः स्वदेशी जागरण मंच

कोरोना टीका को पेटेंट मुक्त करने के स्वदेशी जागरण मंच के अभियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है। करीब एक माह से चल रहे मंच के ''यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन'' डिजिटल हस्ताक्षर अभियान से 13 लाख से अधिक लोग जुड़ गए हैं। विशेष बात कि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा समेत यूरोप के अन्य देश तथा खाड़ी मुल्कों के लोग साथ आए हैं। इस अभियान के पक्ष में हस्ताक्षर करने वाले नौ हजार से अधिक लोग विदेशी हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मंच ने 20 जून को वैश्विक स्तर पर ''जागृति दिवस'' मनाने की तैयारी की है। जिसके तहत देश के 700 से अधिक जिलों में कार्यक्रम करने के साथ देश के बाहर दो हजार से अधिक कार्यक्रम करने की तैयारी है।

स्वदेशी अभियान को मिल रहा अंतरराष्ट्रीय समर्थन

मंच लगातार कोरोना के टीके के साथ ही इससे संबंधित दवाओं को पेटेंट मुक्त करने की मांग कर रहा है। इसे लेकर वैश्विक स्तर पर मुहिम भी चला रखी है। कुछ दिन पहले मंच द्वारा आयोजित वेबिनार में अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति व हावर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. नरेंद्र रुस्तगी के अलावा अमेरिका के कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुई थीं। इस अभियान में मंच द्वारा विभिन्न देश के दूतावास व उच्चायोग में ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है।

बता दें कि पिछले वर्ष चीन के अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ भी मंच ने वैश्विक अभियान चलाया था। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन ने बताया कि इस अभियान से श्रमिक, किसान, उद्योग, विश्वविद्यालय, छात्र व सामाजिक समेत अन्य संगठनों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के साथ इस तरह की मुहिम का असर देखा जा रहा है। जी–7 देशों में खासकर फ्रांस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रयास का समर्थन किया है। इसी तरह यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के सभी हिस्सों के सांसदों, वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेता भी अपनी सरकारों पर दबाव डालने के लिए साथ आए हैं। यह प्रशंसनीय है।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-indigenous-campaign-to-get-corona-vaccine-patent-free-is-getting-international-support-says-swadeshi-jagran-manch-21737833.html

वंचितों को मिले आर्थिक सहायता, मनरेगा का कोष भी बढ़ेः स्व.जा.मं.

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह अपनी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये कोष में ''खासी वृद्धि'' करे और वंचित वर्ग को मुफ्त अनाज के अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मुहैया कराए।

मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में यह सुझाव भी दिया गया कि सरकार को कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों जैसे निर्माण, मत्स्यिकी और बागबानी आदि के लिये ''सॉफ्ट लोन (बिना ब्याज या कम ब्याज दर पर कर्ज)'' के रूप में ''विशिष्ट प्रोत्साहन'' देने पर विचार करना चाहिए।

मंच ने कहा, ''यह एक पूर्व निष्कर्ष है कि स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी और रोजगार के कम अवसरों ने गरीबों के घर के आर्थिक हालात को और खराब किया है, गरीबी का स्तर बढ़ा है और धन के वितरण में असमानता आई है।''

कोरोना से देश में अभूतपूर्व मुश्किल स्थिति में स्वदेशी जागरण मंच का सुझाव है कि मुफ्त अनाज के अलावा समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता पर विचार करने के साथ ही ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना) के कोष में वृद्धि की जाए।

मंच ने यह भी सुझाव दिया है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार ''कुछ और महीनों के लिये'' किया जाना चाहिए और इसका दायरा महामारी प्रभावित अन्य क्षेत्रों के लिये भी बढ़ाया जाना चाहिए।

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/swadeshi-jagran-manch-calls-for-increasing-the-fund-of-mnrega-and-providing-financial-assistance-to-the-underprivileged/articleshow/83283804.cms

वैश्विक सर्व सुलभ टीकाकरण एवं चिकित्सा अभियान

समूचा विश्व कोरोना संक्रमण के भय के साये में जी रहा है, हालांकि वेक्सीनेशन के कारण कुछ राहत है, पर टीकों पर बड़ी कम्पनियों के पेटेंट के कारण ये सबको सुलभ नहीं हैं। ऐसे में कुछ कम्पनियों को पेटेंट से मुनाफा कमाने हेतु असीमित अधिकार देकर करोड़ों लोगों के जीवन के अधिकार पर आंच आये, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। मानव का जीवन का अधिकार सार्वभौम मौलिक अधिकार है। इसी को ध्यान में रखकर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से टीकों व दवाओं को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नालॉजी के हस्तांतरण के लिये एक सघन अभियान– "वैश्विक सर्व सुलभ टीकाकरण एंव चिकित्सा अभियान" चलाया जा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के जोधपुर विभाग संयोजक समीर रायजादा ने अनुसार इजरायल, अमेरिका, इंग्लैंड आदि जिन 6 देशों की वयस्क जनसंख्या का टीकाकरण हो गया है वहाँ कोरोना संकट लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए भारत सहित विश्व की समग्र वयस्क जनसंख्या (लगभग 600 करोड़) का तत्काल टीकाकरण आवश्यक है। कोविड के इलाज से सम्बंधित कई दवाओं का स्थानीय उत्पादन हो रहा है, लेकिन समस्या की गंभीरता के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध मात्रा अत्यधिक अपर्याप्त है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने कोविड के टीकों व औषधियों को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नालॉजी इनके उत्पादन में सक्षम सभी दवा उत्पादकों को सुलभ कराने की मांग करते हुए सघन जन जागरण अभियान छेड़ा है। स्वदेशी जागरण मंच ने देश भर में व देश के बाहर भी टीकों व औषधियों की सर्व सुलभता हेतु "युनिवर्सल एक्सेस टु वेक्सीन्स एण्ड मेडिसिन्स" अर्थात "युवम" (UVAM) के नाम से अभियान चलाया है।

स्वदेशी जागरण मंच राजस्थान के क्षेत्र संयोजक डॉ. धर्मेन्द्र दुबे के अनुसार भारत में भी कम से कम 70 प्रतिशत जनसंख्या के टीकाकरण के लिए लगभग 200 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। इस बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इनकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा और इनके पेटेंट और व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा अधिकार सम्बन्धी बाधाओं–समस्याओं को दूर करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपाय करने की आवश्यकता है।

जनकारी के अनुसार भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ, विगत अक्टूबर में ही इन्हें पेटेंट मुक्त करने का विश्व व्यापार संगठन में जो ट्रिप्स समझौते से छूट का प्रस्ताव रखा उसका 120 देशों ने अब तक समर्थन कर दिया है। स्वदेशी के युवम अभियान ने इस पेटेंट मुक्त वेक्सीन की मांग करते हुए इसका विरोध कर रहे देशों से समेत विश्व व्यापार संघटन से भी आग्रह पूर्वक अपील की है, जिससे कि टीकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कच्चे माल की उपलब्धता, व्यापार रहस्य सहित सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।रेम्डेसीवीर, फेविरेसीर, टोसिलिजुमेब और अन्य आवश्यक दवाओं के उत्पादन और मोलनुपीराविर जैसी नई दवाओं का प्रचुरता से उत्पादन सुनिश्चित किया जाए।

https://www.jagran.com/rajasthan/jaipur-swadeshi-jagran-manch-global-universally-accessible-vaccination-and-medical-campaign-to-make-covid-vaccines-patent-free-21703350.html

स्वदेशी से ही बनेगा भारत संपन्न राष्ट्रः आलोक कुमार

जब तक भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने देश द्वारा निर्मित चीजों को नहीं अपनाएगा तब तक देश संपन्न नहीं हो सकता। देश की संपन्नता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में बनी हुई प्रत्येक वस्तु को हम स्वीकारें और अपनेपन की दृष्टि से देखें। जो अच्छा है उसे अपनाएं, जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को खो देंगे।

उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आलोक कुमार ने स्वदेशी जागरण मंच फरीदाबाद द्वारा आयोजित वैचारिक वेबीनार श्रृंखला में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कही।

इस वेबीनार में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संपर्क प्रमुख सतेंद्र सौरोत ने कार्यक्रम की भूमिका को रखा एवं बताया कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित यह वेबिनार पिछले 16 दिनों से लगातार चल रही है। श्री सौरोत ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीनस एंड मेडिसिंस (यूएवीएम) के नाम से याचिका पर चलाए जा रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस याचिका पर देश भर से साढ़े पांच लाख वहीं हरियाणा से 38 हजार से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस आभासीय श्रंखला में कुल 110 लोग उपस्थित थे। विभाग संयोजक कुणाल राज गोयल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। स्वदेशी जागरण मंच विभाग संपर्क प्रमुख श्री अमरदीप सिंह ने मंच का संचालन किया। वेबीनार में डॉक्टर कृष्ण कांत उपाध्याय, एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, एडवोकेट रामवीर तंवर, दुर्गेश कश्यप, जितेंद्र हल्दिया, हुकम चंद गर्ग, अरविंद नागर एवं अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वेबीनार में भाग लेने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के फरीदाबाद के विभाग संयोजक अमर सिंह सौरोत, गुरुग्राम विभाग संयोजक उमेश आर्य, गुरुग्राम विभाग के सह संयोजक विक्रमादित्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। ❑❑

वैश्विक सर्व सुलभ टीकाकरण व चिकित्सा

Universal Access to Vaccine and Medicines campaign (UAVM)

विश्व जागृति दिवस

पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम

20 जून 2021 11AM

स्वदेशी पत्रिका   डाक तिथि 15–16 जून 2021
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रीय परिषद बैठक (तरंग)

5–6 जून, 2021

सचित्र झलक

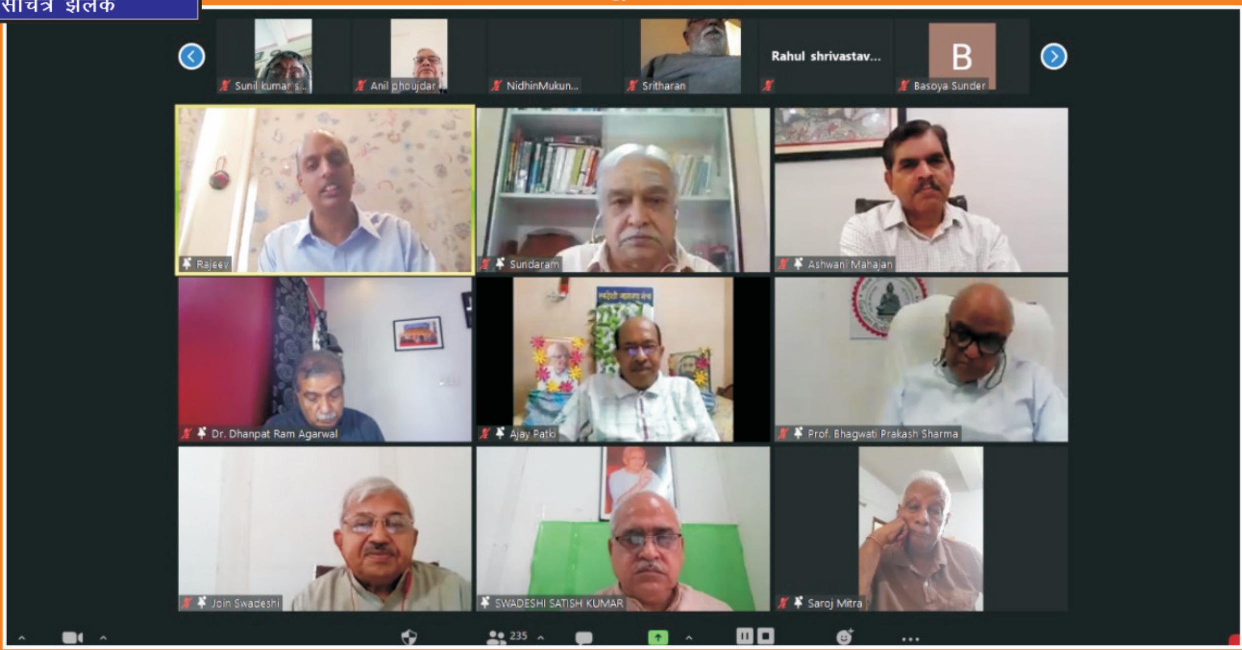

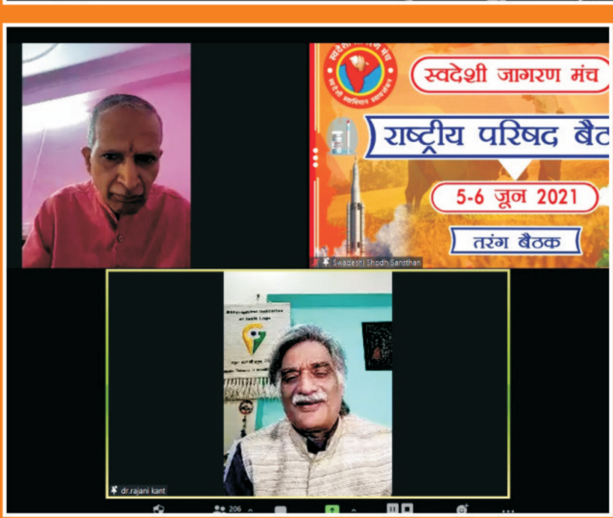

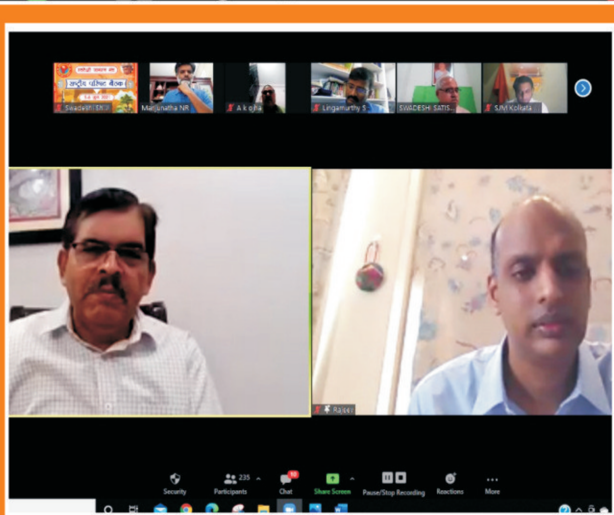

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती